सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 108, नई दिल्ली, शुक्रवार 27 जून 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है।

03 भाजपा द्वारा आपातक़ालीन बंदियों को सम्मानित किया गया

06 भारतीय शिक्षा में पुनर्विचार भाषा

08 अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला, एनएच पर पुलिस पब्लिक धक्का मुक्की

एमसीडी के टोल बूथों को हटाने के लिए एनएचएआई ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जानिए क्या है पूरा मामला

संजय बाटला

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दिल्ली की अंतरराज्यीय सीमाओं से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के टोल बूथ हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एनएचएआई का कहना है कि ये बूथ वाणिज्यिक वाहनों से प्रवेश शुल्क और ग्रीन चार्ज वसूलते हैं, जिससे दिल्ली की सीमाओं पर भयंकर जाम लगता है और राजमार्ग विकास में किए गए निवेश का वांछित परिणाम नहीं मिल रहा है। एनएचएआई ने टोल संग्रह बिंदुओं को सीमा से दूर स्थानांतरित करने और 2015 के ईसीसी आदेश में बदलाव की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाखों यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत दे सकता है।

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अंतरराज्यीय सीमाओं से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा चलाए जा रहे प्रवेश (टोल) बूथों को हटाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

इन बूथों पर नगर निगम द्वारा वाणिज्यिक वाहनों (सीवी) से प्रवेश शुल्क और ग्रीन चार्ज वसूला जाता है। जिसके कारण दिल्ली की सीमाओं पर खासकर दिल्ली में प्रवेश करने वाली लेन में दिन भर यातायात प्रभावित होता है और शाम के समय भयंकर जाम लग रहा है।

दिल्ली से गाजियाबाद और नोएडा को जोड़ने वाला एनएच-9 और दिल्ली-गुरुग्राम को जोड़ने वाला एनएच-48 सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले हाईवे हैं, जिन पर इसका असर साफ दिखता है।

राजमार्ग विकास में किए गए निवेश का नहीं मिल रहा परिणाम: एनएचएआई

प्राधिकरण ने लंबित एमसी मेहता मामले में आवेदन दायर किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की निगरानी कर रहा है और 1980 के दशक से आदेश पारित कर रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार एनएचएआई ने अपने आवेदन में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली से कनेक्टिविटी सुधारने के लिए राजमार्ग विकास में किए गए भारी निवेश से टोल संग्रह बिंदुओं के कारण सीमाओं पर भीड़भाड़ के कारण वांछित परिणाम नहीं मिले हैं।

अधिकारियों ने कहा कि एनएचएआई ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सहित एनसीआर में कई परियोजनाओं का उल्लेख किया है, जिन्हें दिल्ली के लिए नहीं बनाए गए वाहनों के लिए बाईपास के रूप में बनाया गया था।

इन दोनों परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लागू किया गया था। अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चूंकि वाहनों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) का संग्रह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शुरू किया गया था, इसलिए केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इस मामले पर निर्णय ले सकता है।

टोल कलेक्शन प्वाइंट को सीमा से दूर शिफ्ट करने की अपील

इस अपील में यह अनुरोध किया गया है कि टोल कलेक्शन प्वाइंट को सीमा से दूर शिफ्ट किया जाए और 2015 में दिए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) से जुड़े आदेश में बदलाव किया जाए।

अधिकारी के अनुसार ईसीसी सिर्फ कमर्शियल वाहनों से लिया जाता है, टैक्सियों से नहीं लिया जाता है।एमसीडी फिलहाल दिल्ली की सीमाओं पर प्रमुख जगहों पर ईसीसी वसूलती है।इसमें गुरुग्राम का सिरहौल बार्डर, गाजीपुर, बदरपुर, टिकरी और कुंडली आदि शामिल हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली और हरियाणा प्रशासन के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी। अब अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है और एनएचएआई और एमसीडी कितनी जल्दी इन बदलावों को लागू कर पाते हैं।

अगर यह योजना सफल होती है, तो दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्रियों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिल सकती है।दिल्ली की सीमीओं पर 154 टोल बूथ हैं, इसमें से 13 बड़े टोल बूथ हैं।

दिल्ली की बसों में सफर करना होगा आसान, नरेला के लोगों को जल्द मिलेगा बस टर्मिनल

दिल्ली सरकार परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कमर कस चुकी है। इसी माह दिल्ली को 150 नई 'देवी' बसें मिलेंगी, और नरेला के सेक्टर-9 में एक अत्याधुनिक बस टर्मिनल तैयार हो रहा है। इस हाईटेक टर्मिनल में बस-बे, पार्किंग, कैंटीन, शौचालय और इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने परियोजनाओं की समीक्षा की, और बताया कि 'देवी' बस सेवा को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली की जनता को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने कमर कस ली है। एक तरफ दिल्ली को एक नया बस टर्मिनल मिलने जा रहा है।

एक तरफ जहां दिल्ली वालों को इसी माह 150 देवी बसें मिलने जा रही हैं, वहीं जल्द नरेला के सेक्टर-9 में 4000 वर्गमीटर क्षेत्र पर अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनकर तैयार हो रहा है।

यह आधुनिक हाईटेक बस टर्मिनल बहुत जल्द जनता को समर्पित होगा।नरेला बस टर्मिटल से बस संचालन के लिए तीन समर्पित बस-बे, 34 मीटर और 40 मीटर के दो आधुनिक शेड का निर्माण।

बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था, कैंटीन, स्वच्छ एवं सुलभ शौचालय ब्लॉक, सुरक्षित पेयजल के लिए आरओ वाली पानी की व्यवस्था के साथ ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग प्वाइंट भी स्थापित किए गए हैं।

परिवहन मंत्री डा पंकज कुमार सिंह ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की और विभिन्न परियोजनाओं की स्टेट्स रिर्पोट ली।

मंत्री डॉ सिंह ने कहा कि राजधानी के घनी आबादी इलाके में चल रहीं डीटीसी की नौ मीटर लंबी वाली देवी बस सेवा को दिल्लीवासियों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है।

सहकारिता भवन सिरी फोर्ट रोड पर आटो टैक्सी संगठनों द्वारा उन्हें आ रही परेशानियों के लिए की बैठक

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आज भारत सरकार की पहल पर सहकारिता भवन सिरी फोर्ट रोड दिल्ली में अन्य ऑटो टैक्सी संगठनों की ओला उबर रैपीडो की गुलामी से निजात दिलाने के लिए सहकारिता मोबाइल ऐप को लेकर अहम बैठक हुई जिसमें ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने सहकारिता ऐप को लेकर विचार रखें। तथा संगठन भारत सरकार की पहल पर उम्मीद जाहिर की की ओला उबर रैपीडो मोबाइल एप के जरिए दिल्ली समेत देशभर के चालको खून चूसने वाली इन मोबाइल एप कंपनियों को टक्कर देने के लिए केंद्रीय सहायता विभाग की तरफ से सहकारिता मोबाइल एप जल्दी लॉन्च की जाएगी जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मोबाइल ऐप के अधिकारी कर्नल हिमांशु के नेतृत्व में बैठक हई। तथा करनाल हिमांशु जी की तरफ से सहकारिता ऐप में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लेकर अन्य योजनाएं शामिल किए जाने की बाद उन्होंने ऑटो टैक्सी संगठन के प्रतिनिधि मंडल के सामने राखी अर्थात संगठन के माध्यम से चालकों के हितों के देखते हुए पूरी उम्मीद जाहिर किया कि सहकारिता मोबाइल आपके आने से चालकों का भविष्य एवं परिवार का पालन पोषण सुचारू ढंग हो सकेगा अर्थात इस बैठक में संगठन के प्रतिनिधि मंडल में शमिल किशन वर्मा, रवि राठौर, सुमेर अम्बावता, रवि रंजन सुरजीत सिंह, दिलशान, करनजीत गोठवाल, सोनू, हैदर अली, वे अन्य ऑटो टैक्सी चालकों ने सहकारिता मोबाइल एप का जोरदार स्वागत करते हुए भारत सरकार के कदम की सराहना करते हुए आशा व्यक्त किए की इससे ऑटो टैक्सी चालकों को आने वाले सहकारिता मोबाइल ऐप से जुड़ने से कई लाभकारी योजनाओं का फायदा हो सकेगा।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

नोएडा एयरपोर्ट के लिए चलेंगी सिटी बसें, जेवर से बोटेनिकल गार्डन के बीच होगा पहला रूट

जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच आसान बनाने के लिए सिटी बस सेवा शुरू की जा रही है। पहला रूट जेवर से नोएडा के बोटेनिकल गार्डन तक होगा। कुल 500 बसें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में चलेंगी। तीनों प्राधिकरण मिलकर एक संयुक्त एसपीवी बनाएंगे जो रूट तय करेगा और संचालन की देखरेख करेगा। यात्रियों को बस के रूट और समय की जानकारी एक मोबाइल ऐप पर मिलेगी।

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आमजन आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए अब शासन स्तर से कनेक्टिविटी को लेकर फैसला लिया गया है। वह यह है कि जिले के तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में जो सिटी बस सेवा शुरू होनी है। पहला रूट जेवर से नोएडा के बोटेनिकल गार्डन के बीच का होगा।

बाकी रूटों का चयन नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण की बन रही संयुक्त विशेष प्रायोजन संस्था (एसपीवी) करेगी। फिलहाल इस रूट पर पहले प्रति एक घंटे में फिर 45 मिनट के अंतर पर बसें चलेंगी। संबंधित एजेंसी को सबसे पहले इस रूट पर ही बसें चलानी होंगी।

तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में चलेंगी 500 सिटी बसें

तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में 500 सिटी बसें चलाने के लिए मार्च में हुए टेंडर की फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद दो एजेंसियों को चुन लिया गया है। यह टेंडर शहरी परिवहन निदेशालय की तरफ से किया गया है। निदेशालय ने प्राथमिकता वाले रूट की स्थिति तीनों प्राधिकरण से स्पष्ट कर दी है।

नोएडा को 300, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण को 100-100 बसें मिलनी हैं। एसपीवी में तीनों ही प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे। यह प्राधिकरण की सर्वे रिपोर्ट और जरूरत के हिसाब से रूट तय कर बस संचालन का जिम्मा पाने वाली एजेंसी को देंगे। इसके साथ ही बस स्टाप, डिपो व अन्य इंफ्रा प्राधिकरणों को ही तैयार कर एजेंसी को देना होगा।

एप पर मिलेगी रूट और आने वाली बस की जानकारी

बस संचालन के लिए एसपीवी गठन के बाद संचालन की रूपरेखा तैयार होगी। इसमें निर्देशन प्रदेश का शहरी परिवहन निदेशालय देगा। नोएडा-ग्रेनो-यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सिटी बस संचालन को एप से जोड़ने की जरूरत सामने आई है।

यह एप एसपीवी की तरफ से तैयार कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि एप पर बस के रूट, समय आदि की जानकारी मिलेगी। एप से यूपीआइ से भुगतान और नोएडा मेट्रो के साथ संयुक्त कार्ड पर भी विचार होगा।

लहसुन-प्याज खाना चाहिए या नहीं? (पूरे लेख में,, बहुत से प्रमाणों के साथ,, स्पष्ट शास्त्रीय विवेचन)

समाज दो दृष्टिकोण से बनता है। एक तो - 'क्या हो रहा है?', दूसरा, 'क्या होना चाहिये।' जो हो रहा है, उसमें युग और परिवेश की प्राधान्यता होती है। जो होना चाहिये, उसमें शास्त्र की प्राधान्यता होती है। युग एवं परिवेश परिवर्तनशील होने से कभी उन्नति तो कभी अवनति का कारण बनते हैं किन्तु शास्त्र अपरिवर्तनीय एवं कालातीत होने से स्वानुगामी को सदैव उन्नत ही करते हैं। भगवान्-श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं

आहारोऽपि सर्वस्य प्राणिजातस्य
सत्त्वादिगुणत्रयान्वयेन त्रिविधः प्रियो भवति।

प्रत्येक प्राणी की अपने पूर्व संस्कार एवं परिवेश के आधार पर सात्विक (श्रेष्ठ), राजस (सामान्य) एवं तामस (निकृष्ट), ऐसे तीन प्रकार के आहार की अभिरुचि होती है।

भगवान्-श्रीकृष्ण ने कहा -

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः।

आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं -

आहारोऽपि सर्वस्य प्रियस्त्रिविध एव भवति।

केवल मेरा नहीं, आपका नहीं, अपितु 'सर्वस्य' ... सबों का ... सभी देहधारियों का। उसमें जो तामसी आहार है, उसके लक्षण में कहते हैं -

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितञ्च यत।
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम॥
(श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय - १७)

इसमें 'पूति' लक्षण वाले आहार को तामसी जनों का प्रिय बताया गया है। इसका समर्थन कल्किपुराण भी करता है।

पूतिपर्युषितं ज्ञेयं भोजनं तामसप्रियम॥
(कल्किपुराण)

अब पूति का क्या अर्थ है ? जिसमें दुर्गन्ध हो - पूतिदुर्गन्धोपेतम् (रामानुजभाष्य)

आचार्य धनपति इसमें और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, किस प्रकार का दुर्गन्ध ? जैसा लहसुन प्याज में है, उस प्रकार का।

पूतिर्दुर्गन्धि लशुनपलाण्ड्वादि
(धनपतिव्याख्या)

किसी भी कृत्याकृत्य या भक्ष्याभक्ष्य के निर्धारण में सर्वथा शास्त्र और ऋषिवाक्य ही परम प्रमाण होते हैं। प्रमाणक्रम में हम देखते हैं कि उस विषय में वेद भगवान्-क्या कहते हैं ?

मद्यं मांसं च लशुनं पलाण्डुं शिग्रुमेव च।
श्लेष्मातकं विड्वराहमभक्ष्यं वर्जयेन्नरः॥

(रुद्राक्षजाबालोपनिषत्)

इस प्रकार वेद ने निषेध किया। अब उसके बाद स्मृति का स्थान आता है, उन्होंने भी मना किया है।

लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च।
अभक्ष्याणि द्विजातीनां अमेध्यप्रभवानि च॥
(मनुस्मृति, पञ्चम अध्याय)

पलाण्डुं विड्वराहं च छत्राकं ग्रामकुक्कुटम्।
लशुनं गृञ्जनं चैव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत॥
(याज्ञवल्क्य स्मृति, आचाराध्याय)

अब इसके बाद कतिपय इतिहास-पुराण के प्रमाणों पर भी दृष्टि डालें -

मद्यं मांसं तु लशुनं पलाण्डुं शिग्रुमेव च।
श्लेष्मान्तकं विड्वराहं भक्षणे वर्जयेत्ततः॥
(शिवपुराण, विश्वेश्वरसंहिता, अध्याय-२५)

मद्यं मांसं च लशुनं पलाण्डुं शिग्रुमेव च।
श्लेष्मातकं विड्वराहं भक्षणे वर्जयेत्ततः॥
(श्रीमद्देवीभागवतमहापुराण, स्कन्ध - ११, अध्याय - ०७, श्लोक - ४०)

तुम्बकोशातकं चैव पलाण्डुं गृञ्जनं तथा।
छत्राकं लशुनं चैव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत॥
(महाभारत, आश्वमेधिक पर्व)

पलाण्डुं लशुनं शुक्तं निर्यासं चैव वर्जयेत।
(पद्मपुराण, स्वर्गखण्ड, अध्याय - ५६)

पलाण्डुं लशुनं शिग्रुमलाबुं गृञ्जनं पलम्।
भुङ्क्ते यो वै नरो ब्रह्मन्-व्रतं चान्द्रायणं चरेत॥
(पद्मपुराण, ब्रह्मखण्ड, अध्याय - १९)

लशुनं गृञ्जनं चाद्यात्प्राजापत्यादिना शुचिः।
(अग्निपुराण, अध्याय - १६८)

पलाण्डुं लशुनं चैव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत। (कूर्मपुराण)

भूस्तृणं लशुनं भुक्त्वा शिशुकं कृच्छ्रमाचरेत।
(अग्निपुराण, अध्याय - १७*)

उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि लहसुन प्याज खाना केवल वर्जित ही नहीं, अपितु पतनकारी भी है क्योंकि,, अधोगच्छन्ति तामसाः। (श्रीमद्भगवद्गीता)।

लहसुन, प्याज खाने पर कृच्छ्र, प्राजापत्य, चान्द्रायण आदि व्रतों का प्रायश्चित्त निर्देश भी है।

अब देखना यह है कि किसके लिए वर्जित है और किसके लिए नहीं ? तो प्रथम सात्विक मार्ग का आश्रय लेने वाले सभी लोगों के लिए निषिद्ध है। द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के लिये तो सर्वथा निषिद्ध है, शूद्रवर्ण को छूट है क्योंकि उनमें शास्त्रोक्त दृष्ट्या तमोगुण अधिक होता है। ब्राह्मण भी तमोगुणी हो जाये तो वह संस्कार और धृति की दृष्टि से शौद्रलक्षणापन्न होने लगता है। अन्न से रस, रस से वृत्ति, वृत्ति से क्रिया और क्रिया से संस्कार का निर्माण होता है अतएव उत्तम संस्कार हेतु सात्विक अन्न का आश्रय लेना चाहिए।

तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है -

अन्नात्परिस्रुतो रसम्।

मुण्डकोपनिषत् का कथन है - अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्॥

शास्त्रीय सत्वबुद्धि से लहसुन प्याज का समर्थन नहीं किया जा सकता, कोई तमोबुद्धि से ग्रहण करना चाहे तो अलग बात है। आयुर्वेद के जिन कल्पों में रोगनिवारण हेतु शोधित रूप में लहसुन प्याज के सेवन का वर्णन है, वहाँ अपरिहार्य स्थिति में देहरक्षण हेतु कुशल चिकित्सक के कहने पर सविधि ग्रहण करना दोषकारक नहीं है, फिर भी स्वस्थ होने के अनन्तर यथासाध्य भूतशुद्धि एवं प्रायश्चित्त करना चाहिए।

मैदे से बनी डबल रोटी (ब्रेड) खाने वाले सावधान !

आज के समाज में मैदे से निर्मित डबल रोटी का प्रयोग एक आम बात हो गई है। प्रायः सभी वर्गों के लोग नाश्ते में अधिकांशतः डबल रोटी का ही प्रयोग करते हैं परन्तु इस डबल रोटी का अधिक सेवन हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। इससे मोटापा, पित्त की थैली में पथरी, हृदयरोग, बंधकोश, कब्जियत, मधुमेह, आंत्रपुच्छ, आँतों का कैन्सर तथा बवासीर जैसे रोगों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

आयुर्वेद में तो सभी वैद्य कहते हैं, जानते हैं कि मैदा से ये हानियाँ होती हैं लेकिन अभी-अभी डॉ. डेनिस पी. बर्कीट द्वारा मैदेवाली डबल रोटी पर किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि यह आँतों में चिपक जाती है। कुछ चिकित्सकों ने तो आँतों पर इसकी जमने की तुलना सीमेंट से की है। आँतों में इसके जमने से आँतों कीअवशोषण क्षमता तथा आंकुचन-प्रकुंचन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

डबल रोटी बहुत महीन मैदे से बनायी जाती है, जिसमें रेशा जैसी कोई चीज ही नहीं होती। इसी कारण यह आँतों में जाकर जम जाती है। फलतः डबल रोटी का उपयोग करने वाले लोग प्रायः कब्ज के शिकार रहते हैं तथा धीरे-धीरे बदहजमी, गैसट्रिक (पेट में गैस बनने) जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इस प्रकार पाचनतंत्र के दुष्प्रभावित होने से शरीर के अन्य तंत्रों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं।

ओडिशा में भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा

ओडिशा के पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू की जाती है। इस रथयात्रा में भगवान श्रीकृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का श्रृंगार करके भव्य रथों में बैठाकर उनकी रथयात्रा निकाली जाती है। 2025 में यह रथयात्रा 26 से 27 जून तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ के भक्त इस अद्भुत रथयात्रा में शामिल होने के लिए हर साल यहां आते हैं।

भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद जरूर खीचें रथ

भगवान जगन्नाथ के रथ को भक्तों द्वारा खींचने की परंपरा बहुत पुरानी है। भक्त दर्शन करने के बाद बारी-बारी से भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं देखा जाता। कोई भी भक्त अपनी श्रद्धाभाव से भगवान जगन्नाथ का रथ खींच सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर से तीनों रथों को खींचकर भक्त 4 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर लेकर जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने वाला व्यक्ति जीवन-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हर किसी को 13 कदम ही रथ खींचने की अनुमति होती है।

जगन्नाथ मंदिर जाएं तो प्रसाद जरूर खाएं

जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद भी बहुत निराला है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। करीब 500 रसोइए और 300 सहयोगी मिलकर प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तनों को लाइन से एक के ऊपर एक रखा जाता है और नीचे एक ही लकड़ी लगाकर सातों बर्तनों का खाना एक ही आंच में बना दिया जाता है। इसमें सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। धार्मिक मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद खाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है।

नीलचक्र और ध्वज के दर्शन जरूर करें

जगन्नाथ पुरी में आपको हर मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र बने ध्वज के दर्शन जरूर करें। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप यहां लगे ध्वज को जिस तरफ से भी देखेंगे, आपको सुदर्शन चक्र बिल्कुल बीच में ही नजर आएगा। इसके अलावा मंदिर के शीर्ष पर लगे नीलचक्र के दर्शन भी जरूर करें।

केदारनाथ को जाग्रत महादेव भी कहा जाता है..

एक बार एक शिव-भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएँ तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनो बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते है और 6 महीने बंद रहते है। वह उस समय पर पहुचा जब मन्दिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनो की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की - कृपा कर के दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिये। लेकिन वहां का तो नियम है एक बार बंद तो बंद। नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया। बार-बार भगवन शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नही सुनी।

*पंडित जी बोले अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहा के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ढंड पड़ती है। और सभी जन वहा से चले गये। वह वही पर रोता रहा। रोते-रोते रात होने लगी चारो तरफ अँधेरा हो गया। लेकिन उसे विस्वास था अपने शिव पर कि वो जरुर कृपा करेगे। उसे बहुत भुख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उस के पास आया और पास में बैठ गया। पूछा - बेटा कहाँ से आये हो ? उस ने सारा हाल सुना दिया और बोला मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बाते करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गयी। वह बोले, बेटा मुझे लगता है, सुबह मन्दिर जरुर खुलेगा। तुम दर्शन जरुर करोगे।

बातों-बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गयी। सूर्य के मद्धिम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किन्तु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसने देखा पंडित जी आ रहे है अपनी पूरी मंडली के साथ। उस ने पंडित को प्रणाम किया और बोला - कल आप ने तो कहा था मन्दिर 6 महीने बाद खुलेगा ? और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गये। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पुछा - तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आये थे ? जो मुझे मिले थे। 6 महीने होते ही वापस आ गए ! उस आदमी ने आश्चर्य से कहा - नही, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था। मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था।

उन्होंने कहा - लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बन्द करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम छः महीने तक यहाँ पर जिन्दा कैसे रह सकते हो ? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे छः महीने तक जिन्दा रह सकता है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गयी सारी बाते बता दी। कि एक सन्यासी आया था - लम्बा था, बढ़ी-बढ़ी जटाये, एक हाथ में त्रिशुल और एक हाथ में डमरू लिए, मृग-शाला पहने हुआ था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गये। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किन्तु प्रभु के दर्शन ना पा सके, सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किये है। उन्होंने ही अपनी योग-माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया। काल-खंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम

'आप वास्तविकता को आमंत्रित नहीं कर सकते, इसे ही आपके पास आना चाहिए; आप वास्तविकता को नहीं चुन सकते है, इसे ही आपको चुनना चाहिए।"

हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, आनंद हमें प्राप्त करता है जिसकी हम खोज में हैं।

हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते अशांति से बचने के लिए, इसके विपरित शांति ही हमें प्राप्त करती है।

लहर, सागर तक कैसे पहुंचेगी, सागर ही लहर तक पहुंचा हुआ है।

जिस लहर को इसका पता चल जाता है वह ठहर जाती है।

जिसे पता नहीं चलता उसकी खोज जारी रहती है।

इसलिए अपनी जगह ठहरने तथा विश्राम पूर्ण होने पर जोर है।

यह योग है, यह ध्यान है।

जिसे कहीं और चाहिए, जिसे लगता है कहीं और मिलेगा उसमें अस्थिरता तो होती है, व्यग्रता भी होती है।

जल्दी कहीं चला जाऊं, वहां शांति मिल जायेगी, सुख मिल जायेगा।

यह व्यग्रता, यह जल्दबाजी ही बाधक हो जाती है।

यह तो तय है जो आदमी ठहरने के महत्व को समझकर ठहरने की कोशिश करेगा उसकी कसौटी शुरू हो जायेगी।

उसके पास जो भी है या जिनके सहारे वह जीता है वह सब बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ जाने के लिए आतुर- उनके साथ

वह भी स्वयं से दूर जाने के लिए व्यग्र है।

कृष्ण कहते हैं -

₹जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आपही मित्र है

और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आपही शत्रु के सदृश शत्रुता में बर्तता है।। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्।।₹

क्या यह संभव है कि हमारा शरीर, हमारे आंख, कान, चेहरे हमारे वश में रहें?

संभव है अगर हम अपनी जगह पर रुकें तथा भीतर की तरफ विश्राम पूर्ण हों, भली प्रकार से अपने आपमें ठहरे हुए हों बिना किसी तुलना के।

तब दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं।

हम भी ठहरे हैं, हमारा शरीर भी हमारे वश में है।

ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसके व्यक्तित्व में बडी गरिमा होती है।

जो कामना के वश में है, जो अधीर है, उतावला है, जो परनिर्भर है वह दीन-हीन हो जाता है।

यदि वह क्रोधी, लोभी, अहंकारी है तो वह दूसरों को सताता है।

परंतु अहंकार कहां नहीं है!

किसी अहंकार को आक्रामकता पसंद नहीं है।हर अहंकार अपनाया जाना, स्वीकारा जाना ही पसंद करता है।

जो अपने में ठहरता है वह सबको अपना सकता है।

वस्तुतःवह किसी पर मेहरबानी नहीं करता, गहरे में वह अपने ही प्रक्षेपण को अपनाता है। अपने ही दूसरे हिस्से को अपने हृदय से लगाता है।अपना मन ही तो विभाजन का खेल खेल रहा है?

दूसरों के विषय में पूछने पर महर्षि ने कहा -

₹दूसरे कहां हैं?₹

प्रक्षेपण के हृदय में जाने पर व्यक्ति खुद भी हृदय में समा जाता है।

अखंडता आ जाती है।

जब तक चेतना देह में है, देहव्यापी है तब तक यह अंदर बाहर की समस्या रहती है।

केंद्र भीतर है, परिधि बाहर है और आदमी घडी के पेंडुलम की तरह दोनों के बीच झूलता रहता है।

केंद्र को छोड सकता नहीं, परिधि बिना चलता नहीं। इसलिए यह हालत होती है।

दोनों में सर्वथा एक जगह रह सके तो ठीक है परंतु सदा के लिए परिधि पर कोई रह सकता नहीं, सदा के लिए सिर्फ केंद्र में - स्वयं में ही रह सकता है।

सभी योग इसमें सहायता करते हैं।

योगसाधक को परिधि पर जाने, रहने के कारण निपटाने पडते हैं, उसकी आवश्यकता को सीमित करना पडता है।

धीमे-धीमे जैसे जैसे वह अपने केंद्र में स्थित होने लगता है, परिधि पर जाने की जरुरत या बाध्यता कम होने लगती है।

अपने आपमें ठहरने के सारे उत्तम परिणाम घटने लगते हैं।

कृष्ण कहते हैं -ईश्वर सभी के हृदय में विद्यमान है।उसकी शरण में जाने से परम शांति होती है।'

तो हृदय कितना दूर है?

भीतर है, पास है फिर उसे छोड़कर दूर जाने का आग्रह किसलिए?

यह समझना पडता है, कुछ करना पडता है।किये बिना होता नहीं।

इसे बिल्कुल कठिन नहीं होना चाहिए।हृदय भीतर ही है, पास ही है, जहां हैं वही है इसलिए कहीं दूर जाने की जरुरत ही नहीं पड़ती।

आदमी जहां जाना चाहता है, जिससे मिलना चाहता है वह उसीका खुद का प्रक्षेपण है।

यह ऐसा है जैसे दर्पण में मुख देखनेवाला प्रतिबिंब का पीछा करे, उसे ठीक करने में लग जाय।

सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि अपने चेहरे को ठीक किया जाय।जो भी इधर है शरीर, आंख, कान, जीभ आदि।

इसमें कुछ किया जा सकता है, प्रतिबिंब में क्या किया जा सकता है?

बिंब ठीक है तो प्रतिबिंब अपने आप ठीक हो जाता है।उधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।जो कुछ करना है इधर करना है।

यही कारण है जो ज्ञानी कहते हैं -

₹दूसरों को बदलना है तो पहले खुद को बदलना जरूरी है।₹

खुद को बदलना मुश्किल है, दूसरे को बदलना ज्यादा आसान लगता है इसलिए सब यही करते हैं।

मगर यह तो और भी कठिन है।

हमारा ही मन हमारा कहना नहीं मानता तो दूसरे का मन तो और भी ज्यादा दूर है।

जो पास है उसीको ठीक नहीं किया जा सकता तो जो दूर है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है?

दूसरे को अपनाकर शांत, संतुलित, समझपूर्ण बनाया जा सकता है तो पहले स्वयं को तो अपनाये, स्वयं को तो शांत, संतुलित, समझपूर्ण बनाये।

दूसरे को बदलने में दूसरों का विरोध रहता है, स्वयं को बदलने में स्वयं का विरोध रहता है अपनी देह, इंद्रिय, अंतःकरण के रुप में।

मगर साधना यही है।

जो लोग इसे छोडकर दूसरों को सुधारने, बदलने में लगे हैं वे अहंकार से भर जाते हैं।

वहां अहंकार काम करता है।

संघर्ष उसका स्वभाव है।

सही अर्थ में जो शुभचिंतक है वह किसीको बदलने का आग्रह नहीं करता, वह सिर्फ सद्भाव वश जो है उसका लाभ हानि बताता है।

स्वयं कृष्ण ने अर्जुन को बहिर्मुखी होने की जगह अंतर्मुखी होने के लिए प्रेरित किया।जो कुछ बताना संभव था सब बता दिया, अंत में कहा-जो तेरी मर्जी हो वह कर।

₹यथेच्छसि तथा कुरु।"

कोई जोर जबरदस्ती नहीं।

यही तरीका सही है वस्तुस्थिति को साफ कर दिया जाय और अगले के समझने के लिए उस पर छोड दिया जाय।

जबरदस्ती किसीको नहीं समझाया जा सकता। आदमी समझे तो समझे।

कल एक मित्र से बात हो रही थी।उनकी पत्नी अत्यंत उग्र स्वभाव की हैं।

जाहिर है पत्नी को कर्ता माना जाता है इससे तकलीफ़ और अधिक बढ जाती है।

कृष्ण कहते हैं -जीव कर्ता है ही नहीं, प्रकृति के गुण कर्ता हैं।'

इसे वास्तविकता की तरह जाननेवाले बहुत थोडे हैं।

यह ऐसा है जैसे बलवान सिंह, कमजोर हरिन को अपना शिकार बनाये और कोई हरिन पर ही सारे दोष लगाये।

हरिन क्या कर सकता है?

हरिन जीव है, क्रोध रुपी तमोगुण प्रकृति है। प्रकृति बहुत बलवान है।या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रुपेण संस्थिता।

कमजोर जीव, बलवान क्रोध के हाथ में शिकार बन रहा है।

₹देही, गुणों के पाशों से देह से बंधा है।₹

वह मजबूर है।अब प्रकृति के गुण जो करेंगे, जीव को करना ही है।

₹भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारुढानि मायया।।₹

इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता।

जिसका ध्यान जाता है वह फिर इस बंधन से छूटकर स्वतंत्र होने की कोशिश करता है।

कोशिश करने वाले की मदद की जाती है।

यह मदद बहुत कीमती है तथा कृतज्ञता समर्पित करने योग्य है।

इस देश में सत्संग और मार्गदर्शक का महत्व इसीलिए है।सब उपलब्ध है।किसी किसी का ध्यान जाता है, सभीका ध्यान नहीं जाता।

सभी का ध्यान नहीं जाता तो कहा जाता है जब उस पर अनुग्रह होगा तब ध्यान जायेगा।

जीव, भगवान का चुनाव नहीं करता, भगवान, जीव का चुनाव करते हैं।

₹You may not invite Reality, it must come to you;

you may not choose Reality,

it must choose you.₹

तब तो यह बंधनकारी बात हो गयी। फिर तो अपने हाथ में कुछ नहीं।

ऐसी बात नहीं।

उस पर यह सूत्र लागू होता है कि लहर, सागर को खोजने न निकल पडे।

वह जहां है वहां ठहरे तो अंदर बाहर चारों तरफ सागर ही सागर है। कहीं जाने की जरुरत नहीं।

अशांत, शांति की खोज में न भटके।वह खुद को संभाले।

वह पायेगा शांति ही शांति है।

₹Perfect peace is of the Self ₹

₹Peace is your natural state.₹

क्या शांति को ढूंढना पडता है?

जब जब क्षणभंगुर अशांति दूर होती है, स्थायी शांति बार-बार अपने स्थायी स्वरूप का अनुभव कराती रहती है।

उसने हमेशा हमें चुन रखा है।

वह सत्य जो है। आधार जो है।

दिल्ली में शिक्षा-स्वास्थ्य का पुराना वाला हाल होने वाला है, प्राइवेट स्कूल-अस्पताल माफिया की वापसी हो गई है- सौरभ भारद्वाज

मुख्य संवाददाता

नईदिल्ली। दिल्ली सरकार के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में एक महिला मरीज के साथ निर्मम बलात्कार और उसकी मौत को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ''आप'' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस घटना ने बीजेपी सरकार की प्रशासनिक विफलता की पोल खोल दी है। उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से पूछा है कि एक सरकारी अस्पताल में महिला मरीज़ के साथ इतनी हैवानियत कैसे संभव है? क्या अस्पताल के सभी सिक्योरिटी गार्ड और प्रशासन सो रहा था? क्या अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे ख़राब थे और अस्पताल में मरीज़ के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिर से शिक्षा-स्वास्थ्य का पुराना वाला हाल होने वाला है और प्राइवेट स्कूल-अस्पताल माफिया की वापसी हो गई है।

सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को मीडिया बातचीत में कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। मेरी स्मृति में ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीज के साथ दुष्कर्म हो जाए और वह भी इतना निर्मम कि उसकी मृत्यु हो जाए। मृतक मरीज 20 वर्ष की युवती थी, जो आईसीयू में भर्ती थी। वहां उसके साथ दुष्कर्म हुआ। इसके बाद बीजेपी की सरकार ने इस घटना को दबाने और छिपाने की पूरी कोशिश की। अब जबकि वह युवती मर चुकी है, तब भी बीजेपी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और ना तो यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की हैं या नहीं। या फिर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है या नहीं उठाया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से अब तक न तो कोई मुआवजा घोषित किया गया है और ना ही मुख्यमंत्री ने अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई मीटिंग बुलाई। इस घटना को भी दबाने का प्रयास जरूर किया गया। मेरी जानकारी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी अस्पताल में इस तरह की घटना घटी हो। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब दिल्ली के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में एक मरीज के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, हालांकि उसमें मृत्यु नहीं हुई थी। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली में 2013 से पहले वाली व्यवस्था फिर से लौट रही है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति फिर से खराब होने लगी है। सरकारी अस्पतालों और स्कूलों को जानबूझ कर बदहाल किया जा रहा है ताकि प्राइवेट अस्पतालों और स्कूलों की चांदी हो सके। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी शुरू हो रही है और दिल्ली में वही पुरानी व्यवस्था लौट रही है। पिछले 10-11 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो सुधार किए थे, उन्हें अब लगभग शून्य पर लाया जा रहा है।

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा है कि दिल्ली अब फुलेरा पंचायत बन गई है। इससे पहले दिल्ली के अस्पताल में मरीज़ के बलात्कार और मृत्यु की घटना कभी नहीं सुनी गई। 2013 अक्टूबर में कांग्रेस सरकार के समय इसी जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में मरीज़ के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी। क्या फिर वही पुरानी सरकारी व्यवस्था वापिस आ गई है? क्या अब शिक्षा और स्वास्थ्य का पुराने वाला हाल होने वाला है? क्या प्राइवेट स्कूल माफिया और प्राइवेट अस्पताल माफिया की वापसी हो गई है?

दिल्ली भाजपा द्वारा सात जिलों में आयोजित जिला संगोष्ठी में आपातक़ालीन बंदियों को सम्मानित किया

मुख्य संवाददाता/ सुषमा रानी

नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा द्वारा आज सात जिलों में आपातलकाल के 50 साल पूरे होने पर जिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें आपातकाल में बंदियों को सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली में जिला कार्याल में आयोजित संगोष्ठी में पूर्व केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक सतीश उपाध्याय एवं अनिल शर्मा ने प्रदेश मंत्री विनोद बछेती एवं जिला अध्यक्ष रविन्द्र सोलंकी के साथ संगोष्ठी को संबोधित किया और आपातकाल में बंदियों को सम्मानित किया।

पश्चिमी दिल्ली जिला कार्यालय में आयोजित जिला संगोष्ठी में दिल्ली सह प्रभारी डॉ अलका गुर्जर ने जिला अध्यक्ष चन्द्रपाल बख्शी और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष आर्या के साथ संगोष्ठी को संबोधित किया और आपातकाल में बंदियों को सम्मानित किया।

नजफगढ जिला कार्यालय में आयोजित जिला संगोष्ठी में प्रदेश महामंत्री सांसद कमलजीत सहरावत ने जिला अध्यक्ष राज शर्मा गौतम के साथ संगोष्ठी को संबोधित किया और आपातकाल में बंदियों को सम्मानित किया।

उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय में आयोजित जिला संगोष्ठी में प्रदेश महामंत्री सांसद योगेंद्र चंदौलिया और प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता ने जिला अध्यक्ष विनोद सहरावत के साथ संगोष्ठी को संबोधित किया और आपातकाल में बंदियों को सम्मानित किया।

महरौली जिला कार्यालय में आयोजित जिला संगोष्ठी में प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक गजेंद्र यादव ने जिला अध्यक्ष रवीन्द्र सोलंकी के साथ संगोष्ठी को संबोधित किया और आपातकाल में बंदियों को सम्मानित किया।

बाहरी दिल्ली जिला कार्यालय में आयोजित जिला संगोष्ठी में प्रदेश उपाध्यक्ष विनय रावत और भाजपा नेता योगेंद्र आत्रे ने जिला अध्यक्ष रामचंद्र चावरिया के साथ संगोष्ठी को संबोधित किया और आपातकाल में बंदियों को सम्मानित किया।

दक्षिणी दिल्ली जिला कार्यालय में आयोजित जिला संगोष्ठी में वरिष्ठ नेताओं ने जिला अध्यक्ष माया बिष्ठ के साथ संगोष्ठी को संबोधित किया और आपातकाल में बंदियों को सम्मानित किया।

सोमनाथ भारती अपनी पत्नी का मानहानि मामले में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोर्ट को बताया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अदालत को बताया कि आप नेता सोमनाथ भारती हितों के टकराव के कारण मानहानि मामले में अपनी पत्नी लिपिका मित्रा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। लिपिका मित्रा ने सीतारमण के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। सीतारमण के वकील ने तर्क दिया कि भारती का अपनी पत्नी का प्रतिनिधित्व करना हितों का टकराव है।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अदालत को बताया कि आप नेता सोमनाथ भारती हितों के टकराव के कारण मानहानि मामले में कानूनी रूप से अपनी पत्नी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने सीतारमण के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है।

राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सुनवाई 16 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने मामले में 19 मई को सीतारमण को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा था कि आरोपित को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में मानहानिकारक, अपमानजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने और प्रकाशित करने का नया मामला प्राप्त हुआ है। इसकी जांच की जानी चाहिए और इसे पंजीकृत किया जाना चाहिए।

भारती द्वारा उनकी पत्नी मित्रा का प्रतिनिधित्व करना हितों का टकराव

सीतारमण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारती द्वारा उनकी पत्नी मित्रा का प्रतिनिधित्व करना हितों का टकराव है, क्योंकि मित्रा भारती की पत्नी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के भाषण से उनके पति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। अधिवक्ता ने दलील दी कि भारती अपने मामले में पेश नहीं हो सकते और उन्हें अपना वकालतनामा वापस ले लेना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रेफरेंस भेजा जाना चाहिए। भारती ने आवेदन पर बहस करने के लिए समय मांगा है।

सोमनाथ भारती की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप

आवेदन में दावा किया गया है कि सीतारमण ने 17 मई, 2024 को एक प्रेस वार्ता में अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारती की प्रतिष्ठा को धूमिल करना और आम चुनावों में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करना था। शिकायत के अनुसार, ये बयान केवल शिकायतकर्ता और उसके पति को चोट पहुंचाने के इरादे से दिए गए थे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के उम्मीदवार को राजनीतिक लाभ और शिकायतकर्ता के पति को राजनीतिक नुकसान हो।

मानसून में बालों का भरोसेमंद साथी बनी रोज़मेरी – जड़ों से दे गहराई तक पोषण

सुषमा रानी

नई दिल्ली। मानसून का मौसम जहाँ एक ओर सुकून और ताज़गी लेकर आता है, वहीं यह बालों के लिए कई समस्याएं भी पैदा करता है। हवा में लगातार बनी रहने वाली नमी, बार-बार बारिश का संपर्क और बार-बार सिर धोने की आदत बालों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हेयरफॉल जैसी समस्या बढ़ जाती है। लेकिन इस मौसम में एक प्राकृतिक उपाय है जो आपके हेयरकेयर रूटीन को पूरी तरह बदल सकता है—और वह है रोज़मेरी।

मैरिको लिमिटेड की चीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर डॉ. शिल्पा वोरा मानसून में रोज़मेरी और नारियल-आधारित हेयर ऑयल के संयोजन को अपनाने की सलाह देती हैं। यह आज सिर्फ पारंपरिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपाय भी है। पैराशूट एडवांस्ड रोज़मेरी एनरिच्ड कोकोनट हेयर ऑयल एक खास फॉर्मूला है, जिसमें नारियल का पोषण और रोज़मेरी की मज़बूती देने वाली खूबियाँ एक साथ मिलती हैं। यह बालों के टूटने से होने वाले हेयरफॉल को 10 गुना तक कम करने में मदद करता है और बालों को लंबा, घना व चमकदार बनाता है।

रोज़मेरी क्यों है बालों की सबसे अच्छी दोस्त?

मानसून में बाल अक्सर रूखे, बेजान और उलझे हुए हो जाते हैं। ऐसे में रोज़मेरी एक असरदार समाधान बनकर सामने आती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स न सिर्फ बालों के झड़ने को कम करते हैं, बल्कि नई और हेल्दी हेयर ग्रोथ को भी प्रोत्साहित करते हैं। यह बालों की ड्रायनेस को दूर कर उन्हें मुलायम और मैनेज करने में आसान बनाती है।

नारियल का पोषण—जड़ों तक

जहाँ रोज़मेरी बालों को मजबूत बनाती है, वहीं नारियल तेल बालों की जड़ों तक—करीब 10 परतों के अंदर तक जाकर उन्हें गहराई से पोषण देता है। यह न केवल टूटने वाले बालों को बचाता है, बल्कि उनमें नई जान भी भरता है। दोनों मिलकर बालों को अंदर से मजबूत करते हैं, जिससे वे लंबे, घने और चमकदार बनते हैं।

इस फ़ायदे को और पुख्ता बनाने के लिए डॉ. वोरा नियमित रूप से तेल मालिश करने की सलाह देती हैं। सबसे पहले हल्के हाथों से स्कैल्प पर तेल लगाकर मालिश करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। फिर बालों की जड़ों से सिरे तक तेल लगाएं और कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि तेल अच्छी तरह से असर कर सके। यह प्रक्रिया सप्ताह में दो या तीन बार दोहराएं, या फिर अपने बालों की ज़रूरत के अनुसार इसकी आवृत्ति तय करें।

बारिश का मौसम मन को सुकून ज़रूर देता है, लेकिन बालों को इस मौसम में थोड़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। इस मानसून, रोज़मेरी को अपनाइए अपनी स्कैल्प की सबसे अच्छी साथी के रूप में, क्योंकि यह सिर्फ बालों की देखभाल नहीं, बल्कि जड़ों तक पोषण देने का प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है।

छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने में मदद करेगा ''आप'' छात्र संगठन एसैप

मुख्य संवाददाता/ सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर छात्रों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन एसैप ने ऐसे छात्रों की मदद के लिए डीयू के ऑर्ट्स फैकल्टी के बाहर एक एडमिशन हेल्प डेस्क लगाया है, जहां छात्रों को उनकी हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली से बाहर के राज्यों से आकर डीयू के कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को भी अपनी आशंकाओं-सवालों के जवाब के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इनके लिए एसैप ने जोन वार हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इन नंबरों पर कॉल कर छात्र अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। गुरुवार को ''आप'' मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर एसैप के सदस्य ईशना गुप्ता और दीपक बंसल ने यह जानकारी दी।

ईशना गुप्ता ने कहा कि "आप" के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एसैप को लॉन्च कर देश के छात्रों को एक नया विजन दिया है। एसैप के कर्मठ सदस्य 24 घंटे छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्रों का एक-एक दिन कीमती होता है। इसी के मद्देनजर एसैप ने अब तक कई सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया है। जब भी छात्रों की कोई मुश्किल घड़ी आई, एसैप की इकाइयों ने अन्य कॉलेजों के प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई और जीत हासिल की। यदि छात्रों के साथ अन्याय कोई मुद्दा एसैप के सामने आया, तो हमने उसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाया।

ईशना गुप्ता ने बताया कि हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई, उस मुश्किल घड़ी में एसैप ने छात्रों का साथ दिया और आर्थिक मदद भी प्रदान की। जब एसैप के छात्रा वहां गए तो देखा कि छात्र साथी कॉलेज के गेट के बाहर धूप, गर्मी और बारिश में संघर्ष कर रहे थे। एसैप को लगा कि छात्रों को खानपान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह तो बस शुरुआत है। इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए एसैप ने बुधवार को एक नई पहल लॉन्च की है। इसके तहत एसैप ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर एक एडमिशंस हेल्प डेस्क तैयार किया है, जो छात्रों को यूजी और पीजी के दाखिले में मदद करेगा।

दीपक बंसल ने कहा कि डीयू के छात्रों ने एबीवीपी और एनएसयूआई को दो-दो सीटों पर बहुमत दिया, ताकि वे उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज उठा सकें। लेकिन ये प्रतिनिधि न तो उनकी आवाज बन पाए, न ही उनकी समस्याएं उठा पाए। हाल ही में जाकिर हुसैन कॉलेज में आग लगने की घटना इसका उदाहरण है, जहां कोई इमरजेंसी गेट नहीं था, न ही फायर अलार्म या फायर इंस्ट्रूमेंट्स थे। यह डीयू प्रशासन के लिए शर्म की बात है।

दीपक बंसल ने कहा कि एसैप डीयू प्रशासन से मांग करती है कि सभी कॉलेजों में ठंडे पानी के कूलर लगाए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए, फायर सेफ्टी और फायर एग्जिट गेट सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही, डीयू और हॉस्टलों में फीस बढ़ोतरी बंद होनी चाहिए। एसैप का मानना है कि सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए, जैसा कि "आप" के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, स्विमिंग पूल और खेल परिसर की व्यवस्था करके दिखाया। एसैप ने कहा कि यदि डीयू प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता, तो वे जल्द ही डीयू के कुलपति को ज्ञापन सौंपेंगे और प्रदर्शन करेंगे।

सरकार से मांग करेंगे कि वह दिल्ली के पत्रकारों की सुविधाओं के लिए कारगर कदम उठाए - डॉक्टर हर्षवर्धन

वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनियन की तरफ से दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दिया गया ज्ञापन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली के पत्रकारों की मांगों को लेकर, एक ज्ञापन हमारी यूनियन, वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को ज्ञापन दिया गया । आपको पता ही होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जब दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री थे तो पत्रकारों को लेकर, मेडिकल एड बिल लाए थे, जिसे शीला दीक्षित व केजरीवाल सरकार ने तबाह कर दिया था।

ज्ञापन यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार उपाध्याय, राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी, दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष संदीप कुमार शर्मा जी की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दिया गया। इस अवसर पर पत्रकार बलराम शर्मा, मनी आर्य, राजेश खन्ना ईश मालिक, शिवाजी सरकार , महेश ढोंडियाल, महेंद्र, सुमित उपाध्याय, पवन जुनेजा भी मौजूद थे।

डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दिया गया ज्ञापन इस तरह से है ।

1 दिल्ली प्रेस रिपोर्टर्स मेडिकल एड रूल्स 1995 *में संशोधन की मांग - मान्यवर, जिस समय आप दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री थे तो वर्ष 1995 में दिल्ली सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए ये रूल्स अधिसूचित किए गए थे । जिसके तहत पत्रकारों, वे उनके माता पिता, पति या पत्नी , व बच्चों को वे सभी मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी, जो केंद्र या राज्य सरकारों में क्लास वन राजपत्रित अधिकारियो (Group A) को दी जा रही हो । शुरुआत में इन रूल्स का लाभ पत्रकारों व उनके परिवार के सदस्यों को मिलने भी लगा, पर बाद में उन रूल्स में कुछ न कुछ खामियां निकाली जाने लगी , जिससे दिल्ली के पत्रकारों को मेडिकल सुविधाओं को लेने में तरह तरह की दिक्कते आने लगी । मान्यवर, दिल्ली सरकार का DIP यानि सूचना व प्रचार निदेशालय दिल्ली सरकार के मानता प्राप्त पत्रकारों को हेल्थ कार्ड जारी करता है । ये हेल्थ कार्ड दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशालय की तरफ से जारी नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से सरकारी व पैनल वाले प्राइवेट हॉस्पिटल व लैब्स में वे मेडिकल सुविधाएं मिल मिल पाती है, जो प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को हासिल होती है । मान्यवर, केंद्र सरकार के प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो से जुड़े पत्रकारों को भी सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाएं हासिल होती है , जिसके एवज में केंद्र सरकार का स्वास्थ्य महानिदेशालय पत्रकारों से कुछ सालाना राशि लेता है । मान्यवर, यदि, दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य महानिदेशालय, भी दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को हेल्थ कार्ड जारी करके , उन्हें सरकारी व पैनल वाले प्राइवेट हॉस्पिटल व लैब्स में वे सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने लग जाए, जो प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को हासिल है, तो दिल्ली सरकार के मानता प्राप्त पत्रकार भी स्वास्थ्य महानिदेशालय को वह राशि देने को तैयार है, जो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य महानिदेशालय, पीआईबी, से मान्यता प्राप्त पत्रकारों से लेता है । मान्यवर, पिछले 2 वर्ष से दिल्ली सरकार के महानिदेशालय में दिल्ली के कई पत्रकारों के मेडिकल बिल, किसी न किसी तकनीकी कारणों की वजह से लंबित पड़े है । हम आपसे मांग करते है कि उन सभी मेडिकल बिलों का भुगतान सुनिश्चित करवाया जाए

2 दिल्ली के पत्रकारों को पेंशन- देश के ज्यादातर राज्यों, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा ,प्रमुख है, जो अपने राज्य के पत्रकारों को नियमित प्रतिमाह, पेंशन सुविधा देता है । पर देश की राजधानी , दिल्ली के पत्रकार इस सुविधा से वंचित है । दिल्ली के पत्रकार और दिल्ली पत्रकार एक्रीडेशन कमेटी कई बार इस सिलसिले में चर्चा करके इस पेंशन सुविधा को लागू करने की मांग दिल्ली सरकार से कर चुके है, पर कभी भी इस मांग पर अमल नहीं हुआ है । हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट भी इसे लेकर राज्य सरकार को निर्देश(प्रति संलग्न) निर्देश दे चुकी है । मान्यवर, हमारी मांग है कि जो पत्रकार करीब 10 वर्ष से दिल्ली सरकार के सूचना व प्रसारण विभाग से मान्यता प्राप्त है और 60 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु के पत्रकार है, उन्हें नियमित 15,000 (पंद्रह हजार रुपए) पेंशन सुविधा दी जाए । ये सभी उन पत्रकारों को दी जानी चाहिए, जो

आयु व सरकारी मान्यता की समय सीमा में आते हो, पर मौजूदा में वे पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हो या नहीं उन सभी को ये सुविधा मिलनी चाहिए

महोदय, हमे उम्मीद है कि हमारी इन मांगों को आप जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे । आप चाहे तो दिल्ली सरकार से बात करके एक आधिकारिक कमेटी का भी गठन करवा सकती है, जिसमें दिल्ली सरकार के चंद संबंधित अधिकारियों के साथ, हमारी टीम से 2 पत्रकारों को भी शामिल किया जाए और ये कमेटी समयबद्ध अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखे, ताकि पत्रकारों की समस्याओं का कोई सर्वमान्य हल निकल सके । आशा है कि आप हमारी समस्याओं को दिल्ली सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि पत्रकारों की समस्याओं का निदान हो सके ।

इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहां की वर्किंग जनरलिस्ट ऑफ़ इंडिया के पत्रकारों माध्यम से मुझे ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1995 में जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी उस समय दिल्ली के पत्रकारों को अनेक प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती थी। बाद में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ गई और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई इन दोनों सरकारों ने पत्रकारों की सुविधाओं पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। वह सरकार का हिस्सा अब नहीं रहे हैं पर सरकार में बैठे लोगों से मांग करेंगे कि वह दिल्ली के पत्रकारों की सुविधाओं के लिए कारगर कदम उठाएं।

नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में जुटा प्रशासन, इन लोगों को मिली चेतावनी; पकड़े जाने पर वसूला जाएगा जुर्माना

नोएडा स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान और गार्बेज फ्री सिटी में सेवन स्टार रैंकिंग हासिल करने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत, 1 जुलाई से 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों को गीला, सूखा, खतरनाक और मेडिकल कचरा अलग-अलग करके देना अनिवार्य होगा। मिश्रित कचरा देने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, इन जेनरेटरों को अपने परिसर में गीले और सूखे कचरे के निस्तारण के लिए प्लांट लगाना भी अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने पर प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करेगा।

नोएडा। शहर को स्वच्छ रखने और स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल स्थान हासिल करने के लिए नोएडा प्रयास कर रहा है। इस बार गार्बेज फ्री सिटी में सेवन स्टार रैंकिंग हासिल करने के लिए प्रतिभाग कर रहा है। सभी बल्क वेस्ट जेनरेटर अपने-अपने स्तर पर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर एक बनाने में सहयोग दें।

यह अपील बृहस्पतिवार को जन स्वास्थ्य विभाग परियोजना अभियंता गौरव बंसल ने सेक्टर-91 स्थित पंचशील बालक इंटर कालेज सभागार में होटल/रेस्टोरेन्ट, मार्केट एसोसिएशन एवं बल्क वेस्ट जेनरेटर्स की बैठक में की। उन्होंने 100 किलोग्राम से अधिक कूडा संग्रह करने वाले बल्क वेस्ट जेनरेटरों से चेतावनी भी दी कि एक जुलाई से किसी का मिक्स वेस्ट नहीं लिया जाएगा।

गीले कूड़े, सूखे कूड़े, हैजाऱडस वेस्ट एवं मेडिकल वेस्ट में अलग-अलग सेग्रीगेट करके दें। यदि कचरा सेग्रीगेट कर नहीं दिया जाता है तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक बल्क वेस्ट जेनरेटर्स के यहां पर निरीक्षण होगा, क्योंकि प्रत्येक बल्क वेस्ट जेनरेटर्स को गीला व सूखा कचरा निस्तारण करने के लिए परिसर में प्लांट लगाना अनिवार्य है।

अभी चार दिन का समय है, यदि वह चाहे तो प्राधिकरण टीम से कचरा सेग्रीगेट करने का प्रशिक्षण ले सकते है, जिसमें अधिकारियों की ओर से उनका सहयोग किया जाएगा। गाईडेड फाच्यून समिति प्रबंधक पारूल रौथाण की ओर से प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बल्क वेस्ट जेनरेटर्स के दायित्वों के विषय में बताया गया।

किस तरह वह अपने कचरे को गीले एवं सूखे कूड़े में अलग-अलग सेग्रीगेट करें। गीले कचरे को स्वयं किस तरह से निस्तारण करें। इस मौके पर स्वच्छ सर्वेक्षण के मानकों एवं कचरे के सेग्रीगेशन के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी। बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा क्लस्टर आधारित प्लांट की योजना तैयार की गई है।

योजना में कोई भी प्रतिभाग कर सकता है। क्लस्टर आधारित प्लांट लगाने हेतु भूमि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु प्लांट लगाने एवं संचालन का सम्पूर्ण व्यय प्रतिभागी को वहन करना होगा।

इस मौके पर ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने पूर्व में सभी बल्क वेस्ट जेनरेटर्स को नोटिस जारी कर नियमों के अनुपालन के लिए सूचित किया जा चुका है। परन्तु कोई सुधार न होने के कारण अब प्राधिकरण बल्क वेस्ट जनरेटर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इस मौके पर सहायक परियोजना अभियंता उमेश चंद और राहुल गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहे।

अभेद होगी नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

गाजियाबाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विश्वस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा कवच को मजबूती देने के लिए एयरपोर्ट परिसर की चारदीवारी के अंदर ही सात फीट की नई चारदीवारी रनवे की सुरक्षा के लिए तैयार की गई है।

यहीं नहीं इस चारदीवारी पर कटीले तारों के जाल के बाद करंट देने के लिए दो फीट ऊंचाई तक 13 नंगे तारों का जाल बनाया गया। उसके अलावा भी 360 डिग्री कवर करने वाले कैमरों के अलावा एआइ से लैस हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए हैं।

बम निष्क्रिय करने की क्षमता रखने वाले रोबोटिक सिस्टम को एयरपोर्ट पर तैनात किया जा चुका है। बैलिस्टिक सुरक्षा से लैस मार्क्समैन बख्तरबंद एसयूवी भी तैनाती के लिए तैयार हैं। अधिकारियों ने बताया नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) देशभर के एयरपोर्ट और विमान परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बीसीएएस की स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार विश्वस्तरीय सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बीसीएएस की एसओपी के अनुसार एयरपोर्ट पर रनवे की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जिसमें रनवे की सुरक्षा के लिए अलग से चारदीवारी और कटीले तारों की बाढ़ के अलावा नंगे तारों की बाढ़ भी लगाई गई है।

4200 मीटर का रनवे 100 प्रतिशत कैमरों की नजर में रहे, इसके लिए प्रत्येक 50 मीटर पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए है। साथ ही प्रत्येक 100 मीटर पर 360 डिग्री नजर रखने के लिए भी अलग से कैमरे लगाने का काम पूरा कर लिया गया है।

सीआइएसएफ के जवान एयरपोर्ट की सुरक्षा में रहेंगे तैनात एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही 1030 सीआइएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) जवानों की तैनाती के लिए स्वीकृत कर चुका है।

कमीश्नरेट पुलिस पुलिस के 131 पुलिस कर्मियों को भी एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए विशेष ट्रेनिंग के लिए लखनऊ भेजा गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट के निजी सुरक्षा कर्मियों को भी सुरक्षा में लगाए जाएंगे।

आपात स्थिति से निपटने को तैनात रहेंगी मार्कसमैन बख्तरबंद गाड़ी सीआइएसएफ के जवानों की तैनाती के साथ ही क्विक रिएक्शन टीम को आतंकी हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए बख्तरबंद एसयूवी वाहनों को सौंपा जाएगा।

इन बख्तरबंद वाहनों में बी-6 स्तर की बैलिस्टिक सुरक्षा के लिए 270 डिग्री रेंज के साथ गन बुर्ज पर मशीनगन लगी होगी। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को ग्रेनेड और माइंस से भी सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही मल्टी लेयर्ड बुलेटप्रूफ ग्लास से लैस होगी।

यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैनात रहेगा रोबोटिक सिस्टम एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेहद कम समय में संदिग्ध वस्तु या बम का पता लगाते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय करने की क्षमता वाले रोबोटिक सिस्टम का ट्रायल भी पूरा कर लिया है।

मिनी रिमोटली आपरेटेड व्हीकल (एमआरओवी) को एयरपोर्ट के संचालन से पहले सुरक्षा एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।

स्मार्ट मीटर लगाने के दो महीने बाद भी नहीं आ रहे हैं बिल? जानें विद्युत विभाग ने क्या कहा

गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में मई में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से दो महीने से बिजली के बिल नहीं मिले हैं, जिससे उपभोक्ता परेशान हैं। उन्हें चिंता है कि एक साथ बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए मीटरों का डेटा अभी तक सिस्टम में अपलोड नहीं हो पाया है। स्थानीय लोग इस समस्या के शीघ्र समाधान और समय पर बिल जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें आर्थिक परेशानी न हो।

गाजियाबाद। नंदग्राम क्षेत्र के बी और सी ब्लॉक में विद्युत विभाग द्वारा मई माह में पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। लेकिन दो महीने होने के बाद भी अब तक उपभोक्ताओं को बिजली के बिल नहीं मिले हैं। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। तब से किसी प्रकार का बिजली बिल प्राप्त नहीं हुआ है। इससे उपभोक्ता असमंजस में हैं कि आने वाले समय में उन्हें कितना भुगतान करना होगा। लोगों के मुताबिक विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि नए स्मार्ट मीटरों का डेटा अब तक सिस्टम में अपलोड नहीं हो पाया है। जिस कारण बिल तैयार नहीं किए जा सके हैं।

स्थानीय लोगों ने शीघ्र समाधान की मांग की

हालांकि, उपभोक्ताओं को चिंता सता रही है कि बिल एक साथ आने पर उन्हें एकमुश्त बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। जिससे आर्थिक समस्या बढ़ सकती है। स्थानीय लोगों ने विभाग से मांग की है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए और समय पर बिल जारी करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

सरकार से मांग करेंगे कि वह दिल्ली के पत्रकारों की सुविधाओं के लिए कारगर कदम उठाए - डॉक्टर हर्षवर्धन

वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनियन की तरफ से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ज्ञापन दिया

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली, दिल्ली के पत्रकारों की मांगों को लेकर, एक ज्ञापन हमारी यूनियन, वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को ज्ञापन दिया गया । आपको पता ही होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जब दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री थे तो पत्रकारों को लेकर, मेडिकल एड बिल लाए थे, जिसे शीला दीक्षित व केजरीवाल सरकार ने तबाह कर दिया था। ज्ञापन यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार उपाध्याय, राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी, दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष संदीप कुमार शर्मा जी की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दिया गया। इस अवसर पर पत्रकार बलराम शर्मा, मनी आर्य, राजेश खन्ना ईश मालिक, शिवाजी सरकार, महेश ढोंडियाल, महेंद्र, सुमित उपाध्याय, पवन जुनेजा भी मौजूद थे।

डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दिया गया ज्ञापन इस तरह से है ।

1. दिल्ली प्रेस रिपोर्टर्स मेडिकल एड रूल्स 1995 में संशोधन की मांग- मान्यवर, जिस समय आप दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री थे तो वर्ष 1995 में दिल्ली सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए ये रूल्स अधिसूचित किए गए थे । जिसके तहत पत्रकारों, वे उनके माता पिता, पति या पत्नी , व बच्चों को वे सभी मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी, जो केंद्र या राज्य सरकारों में क्लास वन राजपत्रित अधिकारियो (Group A) को दी जा रही हो । शुरुआत में इन रूल्स का लाभ पत्रकारों व उनके परिवार के सदस्यों को मिलने भी लगा, पर बाद में उन रूल्स में कुछ न कुछ खामियां निकाली जाने लगी , जिससे दिल्ली के पत्रकारों को मेडिकल सुविधाओं को लेने में तरह तरह की दिक्कते आने लगी । मान्यवर, दिल्ली सरकार का DIP यानि सूचना व प्रचार निदेशालय दिल्ली सरकार के मानता प्राप्त पत्रकारों को हेल्थ कार्ड जारी करता है । ये हेल्थ कार्ड दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशालय की तरफ से जारी नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से सरकारी व पैनल वाले प्राइवेट हॉस्पिटल व लैब्स में वे मेडिकल सुविधाएं मिल मिल पाती है, जो प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को हासिल होती है । मान्यवर, केंद्र सरकार के प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो से जुड़े पत्रकारों को भी सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाएं हासिल होती है , जिसके एवज में केंद्र सरकार का स्वास्थ्य महानिदेशालय पत्रकारों से कुछ सालाना राशि लेता है । मान्यवर, यदि, दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य महानिदेशालय, भी दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को हेल्थ कार्ड जारी करके , उन्हें सरकारी व पैनल वाले प्राइवेट हॉस्पिटल व लैब्स में वे सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने लग जाए, जो प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को हासिल है, तो दिल्ली सरकार के मानता प्राप्त पत्रकार भी स्वास्थ्य महानिदेशालय को वह राशि देने को तैयार है, जो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य महानिदेशालय, पीआईबी, से मान्यता प्राप्त पत्रकारों से लेता है । मान्यवर, पिछले 2 वर्ष से दिल्ली सरकार के महानिदेशालय में दिल्ली के कई पत्रकारों के मेडिकल बिल, किसी न किसी तकनीकी कारणों की वजह से लंबित पड़े है । हम आपसे मांग करते है कि उन सभी मेडिकल बिलों का भुगतान सुनिश्चित करवाया जाए।

2. दिल्ली के पत्रकारों को पेंशन - देश के ज्यादातर राज्यों, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा ,प्रमुख है, जो अपने राज्य के पत्रकारों को नियमित प्रतिमाह, पेंशन सुविधा देता है । पर देश की राजधानी , दिल्ली के पत्रकार इस सुविधा से वंचित है । दिल्ली के पत्रकार और दिल्ली पत्रकार एक्रीडेशन कमेटी कई बार इस सिलसिले में चर्चा करके इस पेंशन सुविधा को लागू करने की मांग दिल्ली सरकार से कर चुके है, पर कभी भी इस मांग पर अमल नहीं हुआ है । हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट भी इसे लेकर राज्य सरकार को निर्देश(प्रति संलग्न) निर्देश दे चुकी है । मान्यवर, हमारी मांग है कि जो पत्रकार करीब 10 वर्ष से

दिल्ली सरकार के सूचना व प्रसारण विभाग से मान्यता प्राप्त है और 60 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु के पत्रकार है, उन्हें नियमित 15,000 (पंद्रह हजार रुपए) पेंशन सुविधा दी जाए । ये सभी उन पत्रकारों को दी जानी चाहिए, जो आयु व सरकारी मान्यता की समय सीमा में आते हो, पर मौजूदा में वे पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हो या नहीं उन सभी को ये सुविधा मिलनी चाहिए। महोदय, हमे उम्मीद है कि हमारी इन मांगों को आप जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे । आप चाहे तो दिल्ली सरकार से बात करके एक आधिकारिक कमेटी का भी गठन करवा सकती है, जिसमें दिल्ली सरकार के चंद संबंधित अधिकारियों के साथ, हमारी टीम से 2 पत्रकारों को भी शामिल किया जाए और ये कमेटी समयबद्ध अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखे, ताकि पत्रकारों की समस्याओं का कोई सर्वमान्य हल निकल सके । आशा है कि आप हमारी समस्याओं को दिल्ली सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि पत्रकारों की समस्याओं का निदान हो सके । इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहां की वर्किंग जनरलिस्ट ऑफ़ इंडिया के पत्रकारों माध्यम से मुझे ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1995 में जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी उस समय दिल्ली के पत्रकारों को अनेक प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती थी। बाद में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ गई और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई इन दोनों सरकारों ने पत्रकारों की सुविधाओं पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। वह सरकार का हिस्सा अब नहीं रहे हैं पर सरकार में बैठे लोगों से मांग करेंगे कि वह दिल्ली के पत्रकारों की सुविधाओं के लिए कारगर कदम उठाएं।

नशे की लत को दूर भगाना भारत देश को स्वास्थ्य बनाना : डॉ हृदयेश कुमार

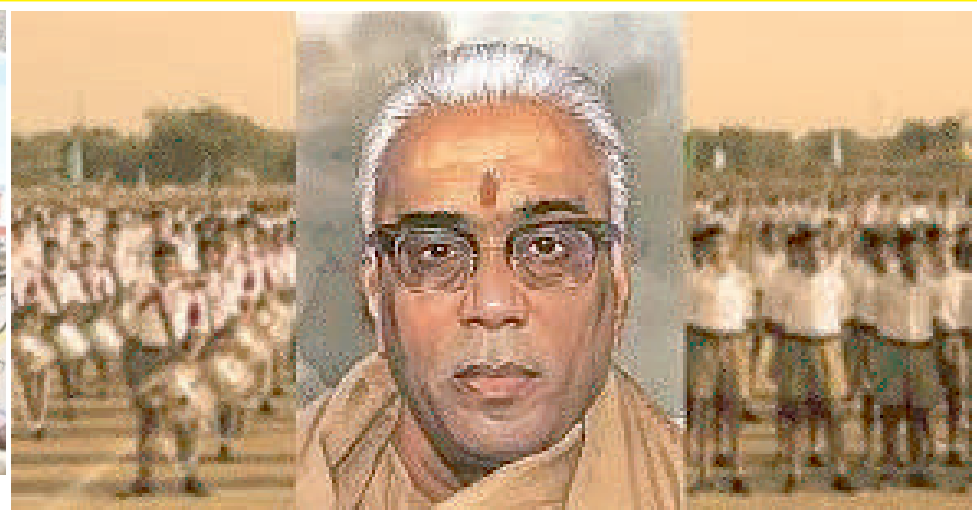

फरीदाबाद। सीता राम सैक्टर 3 फरीदाबाद में अंतरास्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर स्वास्थ्य के लिए Vitamin-B12 की कमी और बचाव पर विशेष चर्चा डॉ हृदयेश कुमार

हर साल 26 जून को 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को नशे की लत और गैरकानूनी ड्रग्स के व्यापार के खतरों के बारे में जागरूक करना है।

नशे के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना।

नशे की रोकथाम और इलाज के बारे में जानकारी देना।

नशे की गिरफ्त में आए लोगों को मदद और पुनर्वास देना।

देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और नशे के खिलाफ सख्त कानून बनाना।

युवाओं और समाज को नशे से बचाने के लिए प्रोत्साहित करना।

।इस दिन का उद्देश्य लोगों में नशे की लत के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना, इलाज और पुनर्वास को समर्थन देना, और देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है

स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

युवाओं और अभिभावकों के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं

देशभर में सरकारी और गैर-सरकारी पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां नशा पीड़ितों को इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा मिलती है।

विटामिन B12 की कमी से शरीर में कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जिनमें थकान, कमजोरी, सुन्नपन, झुनझुनी, याददाश्त की समस्या, और मूड में बदलाव शामिल हैं. गंभीर मामलों में, यह एनीमिया, तंत्रिका क्षति, और हृदय संबंधी समस्याओं का कारण हो सकता है

विटामिन B12 की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे एनीमिया होता है, और थकान और कमजोरी महसूस होती है

यह कमी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हाथों और पैरों में सुन्नता और झुनझुनी हो सकती है.

विटामिन B12 की कमी से याददाश्त, एकाग्रता, और सोचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है.

अवसाद, चिड़चिड़ापन, और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी विटामिन B12 की कमी से जुड़ी हो सकती हैं

विटामिन B12 की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे एनीमिया होता है

गंभीर मामलों में, विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका क्षति हो सकती है, जिससे चलने में परेशानी, मांसपेशियों में कमजोरी, और अन्य तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती हैं

विटामिन B12 की कमी से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है

विटामिन B12 की कमी से त्वचा का पीला पड़ना, जीभ में सूजन, मुंह के छाले, और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है.

यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है

हाथ-पैर में झनझनाहट, मुंह में छाले होना या थकान जैसे लक्षण विटामिन-बी12 की कमी के साधारण लक्षण (Vitamin-B12 Deficiency Symptoms) हैं। लेकिन एक लक्षण ऐसा भी है, जिसपर लोगों का ध्यान काफी कम जाता है। रात में दिखने वाला यह लक्षण विटामिन-बी12 की कमी का प्रमुख संकेत हो सकता है।

Vitamin-B12 की कमी के कारण कई परेशानियां हो सकती हैं

कुछ लक्षणों की मदद से विटामिन-बी12 की कमी को पूरा किया जा सकता है

विटामिन-बी12 की कमी दूर करने के लिए कुछ फूड्स को डाइट में शामिल करना चाहिए

सेब विटामिन बी12 का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, खासकर यदि आप छिलके के साथ खाते हैं

केले में विटामिन बी12 के साथ-साथ कैल्शियम, मिनरल्स और पोटैशियम भी होता है

पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है जो विटामिन बी12 का एक अच्छा स्रोत है

मशरूम, खासकर जंगली मशरूम, विटामिन बी12 का एक अच्छा स्रोत है.

चुकंदर में विटामिन बी12 के साथ-साथ आयरन, पोटैशियम और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं

आलू में भी थोड़ी मात्रा में विटामिन बी12 पाया जाता है.

ब्लूबेरी में विटामिन बी12 के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं.

संतरे में नेचुरल रूप से विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में होता हैं।

विटामिन-बी12 की कमी होना कोई साधारण समस्या नहीं है। इसे नजरअंदाज करने से शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। दरअसल, विटामिन-बी12 की कमी के कारण कमजोरी, हर वक्त थकान, खून की कमी, हाथ-पैर में झनझनाहट, शरीर पीला पड़ना, मुंह में छाले, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स जैसी परेशानियां (Vitamin-B12 Deficiency Symptoms) हो सकती हैं। इसलिए विटामिन-बी12 की कमी के लक्षणों को इग्नोर करने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।

हालांकि, इसका एक लक्षण और है, जो अक्सर सिर्फ रात के समय ही नजर आता है। हम बात कर रहे हैं रात में बहुत ज्यादा पसीना आना (Night Sweats)। अगर आप रात में बिना किसी वजह पसीने से तरबतर हो जाते हैं, तो यह विटामिन-बी12 की कमी का संकेत हो सकता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। विटामिन-बी12 की कमी को डाइट (Vitamin-B12 Rich Foods) और सप्लीमेंट्स की मदद से पूरा किया जा सकता है। आइए जानें इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए।

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स (Milk & Dairy Products)

दूध, दही, पनीर और चीज जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन-बी12 भरपूर मात्रा में होता है। ये शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन-बी12 का एक अच्छा विकल्प हैं। रोजाना एक गिलास दूध या एक कटोरी दही खाने से शरीर में विटामिन-बी12 की जरूरत पूरी करने में मदद मिलती है।

ये 5 संकेत चीख-चीखकर बताते हैं शरीर में हो गई है Vitamin-B12 की कमी, पहली फुरसत में भागें डॉक्टर के पास

फोर्टिफाइड फूड्स (Fortified Foods)

क्योंकि विटामिन-बी12 के सबसे बेहतरीन सोर्स नॉन-वेजिटेरियन फूड्स ही है, शाकाहारी लोगों के लिए फूड्स में अलग से विटामिन-बी12 मिलाया जाता है। इन्हें फोर्टिफाइड फूड्स कहा जाता है। फोर्टिफाइड सीरियल्स, सोया मिल्क और नट्स जैसे फूड आइटम्स विटामिन-बी12 का अच्छा सोर्स साबित हो सकते हैं। बाजार में मिलने वाले कुछ ब्रांड्स के दूध और ब्रेड में भी बी12 मिलाया जाता है, जो शरीर की जरूरतों को पूरा कर सकता है।

विटामिन बी12 के शाकाहारी स्रोतः

दूध और डेयरी उत्पादः

दूध, दही, पनीर और छाछ जैसे डेयरी उत्पाद विटामिन बी12 के अच्छे स्रोत हैं। Health Shots के अनुसार

फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थः

कुछ अनाज, सोया दूध, बादाम का दूध और अन्य प्लांट-बेस्ड दूध विटामिन बी12 से फोर्टिफाइड होते हैं।

पोषक खमीरः

पोषण खमीर एक प्रकार का खमीर है जिसे विशेष रूप से भोजन के लिए उगाया जाता है और यह विटामिन बी12 का एक अच्छा स्रोत है।

शैवालः

कुछ प्रकार के शैवाल, जैसे नोरी, में विटामिन बी12 पाया जाता है। PMC के अनुसार

मशरूमः

कुछ प्रकार के मशरूम, जैसे कि शिटाके, में भी विटामिन बी12 पाया जाता है। PMC के अनुसार

शाकाहारी लोगों को विटामिन बी12 की कमी से बचने के लिए, उपरोक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने या विटामिन बी12 की खुराक लेने की सलाह दी जाती है।

सड़क की जगह रेलवे ट्रैक पर महिला ने चला दी गाड़ी, सोशल मीडिया वीडियो वायरल होने के बाद लोग कर रहे कमेंट्स

परिवहन विशेष न्यूज

सामान्य स्थिति में लोग अपनी कार को सड़कों पर ही चलाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गाड़ी को सड़क की जगह रेलवे ट्रैक पर चलाते हुए दिखाया (woman drives car on railway track) गया है। वीडियो अपलोड होने के बाद लोग किस तरह से कमेंट कर रहे हैं।

नई दिल्ली। भारत में सड़कों की स्थिति पिछले कुछ सालों में काफी बेहतर हो गई है। भले ही सड़कों के अनुपात में वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में लोग कार को सड़क पर ही चलाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गाड़ी को सड़क पर नहीं बल्कि रेलवे ट्रैक पर चलाते हुए दिखाया (woman drives car on railway track) जा रहा है। इस पर लोग किस तरह के कमेंट कर रहे हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

रेलवे ट्रैक पर चलाई गाड़ी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें गाड़ी को सड़क पर चलाने की जगह रेलवे ट्रैक पर चलाते हुए दिखाया गया है। जानकारी के मुताबिक यह गाड़ी एक महिला चला रही है।

कहां का है वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल के ट्रैक पर गाड़ी के आने के कारण ट्रेन सेवा भी बाधित हुई है। वीडियो को देखने पर समझ आ रहा है कि ट्रैक पर चल रही गाड़ी किआ सोनेट है। इस वीडियो को हैदराबाद का बताया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो

सोशल मीडिया पर वीडियो को अपलोड करने के बाद ही यह वायरल हो रही है। सिर्फ कुछ घंटों में ही इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है। इसी के साथ ही लोग कई मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं।

कमेंट में बोल रहे लोग

वीडियो के वायरल होने के बाद लोग मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गलती से मिस्टेक हो गई। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि वो स्त्री कुछ भी कर सकती है। वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए कुछ महिलाएं ऐसी गलती करने वाली महिला को पकड़ने की मांग भी कर रही हैं। कुछ लोग मजेदार कमेंट करते हुए लिख रहे हैं कि यह प्राइवेट वंदे भारत है तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि यह जीटीए गेम खेला जा रहा है।

स्कूटर और बाइक पर क्यों नहीं लगाया जाता टोल टैक्स, यहां समझें सभी सवालों के जवाब

परिवहन विशेष न्यूज

दो पहिया वाहन टोल छूट : भारत में सड़कों पर कई तरह के वाहनों का उपयोग किया जाता है, जिनमें बड़ी संख्या में टू व्हीलर्स भी शामिल होते हैं। स्कूटर और बाइक पर क्यों Toll Tax नहीं लिया जाता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में रोजाना बड़ी संख्या में लोग दो पहिया वाहनों का उपयोग करते हैं। स्कूटर और बाइक का उपयोग हाइवे पर भी किया जाता है। लेकिन नेशनल हाइवे पर कार, बस, ट्रक से तो Toll Tax लिया जाता है पर किन कारणों से दो पहिया वाहनों को इससे छूट (toll exemption two-wheelers) दी जाती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

क्यों लिया जाता है Toll Tax

अगर आप किसी भी नेशनल हाइवे या एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं तो आपको कुछ दूरी तय करने के बाद टोल प्लाजा मिलता है, जहां पर आपके वाहन पर Toll Tax लगाया जाता है। यह ऐसा टैक्स होता है जो आपको उस सड़क पर चलने के लिए देना होता है। आमतौर पर एनएचएआई के हाइवे और एक्सप्रेस वे पर केंद्र सरकार की ओर से ही टैक्स को वसूल किया जाता है।

दो पहिया वाहन पर क्यों नहीं लगाया जाता टैक्स

देश में सिर्फ चार पहिया या उससे बड़े वाहनों से ही Toll Tax को वसूला जाता है। लेकिन कभी भी स्कूटर या बाइक जैसे टू व्हीलर्स से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो वाहन चलते हुए सड़क पर जितनी ज्यादा जगह लेता है उससे उसी अनुपात के मुताबिक टोल टैक्स लिया जाता है। लेकिन दो पहिया वाहन सड़क पर चलते हुए काफी कम जगह लेते हैं, इसलिए इन पर किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं लगाया गया है।

कम जगह लेने वाले मुख्य कारण के साथ ही दो पहिया वाहन का उपयोग कार के मुकाबले कम दूरी तक के लिए किया जाता है और इसका उपयोग करने वाले अधिकतर लोग निम्न और मध्य वर्ग से आते हैं। इसलिए भी सरकार की ओर से अभी तक स्कूटर और बाइक का उपयोग करने पर टोल टैक्स नहीं लिया जाता।

कहां लगता है टोल टैक्स

आमतौर पर देश में अधिकतर हाइवे और एक्सप्रेस वे पर दो पहिया वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन कुछ ऐसे एक्सप्रेस वे भी हैं जहां पर इनसे टोल को वसूल किया जाता है। जिनमें दिल्ली से आगरा के बीच और आगरा से लखनऊ के बीच बने एक्सप्रेस वे हैं, जहां पर दो पहिया वाहन चलाने पर टोल

किआ सिरोस के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की अग्रिम भुगतान के बाद जाएगी कितनी ईएमआई

परिवहन विशेष न्यूज

कार वित्त योजना : साउथ कोरिया की वाहन निर्माता Kia की ओर से भारतीय बाजार में Compact SUV के तौर पर Kia Syros को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment देने के बाद कितने रुपये महीने की EMI देनी (Kia Syros Down Payment and EMI) होगी। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में साउथ कोरिया की वाहन निर्माता Kia की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी के तौर पर Kia Syros को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Kia Syros Price

किआ की ओर से सिरोस एसयूवी को सब फोर मीटर एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इसके बेस वेरिएंट के तौर पर HTK Turbo Petrol को उपलब्ध करवाया जाता है। इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 9.50 लाख रुपये है। इस एसयूवी को अगर दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 66 हजार रुपये आरटीओ और करीब 35 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। इसके साथ ही अन्य खर्च और फास्टैग मिलाकर करीब सात हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद Kia Syros on road price करीब 10.62 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 8.62 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 8.62 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 13878 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार

अगर आप 9 फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 8.62 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 13878 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Kia Syros के लिए करीब 3.03 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 13.65 लाख रुपये हो जाएगी।

किनसे है मुकाबला

Kia की ओर से Syros को कंपनी सब फोर मीटर एसयूवी के तौर पर ऑफर करती है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Renault Kiger, Maruti Breeza, Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Venue, Nissan Magnite, Mahindra XUV 3XO जैसी SUVs के साथ होता है।

क्या हाइवे उपयोग करने के लिए टू व्हीलर्स को देना होगा टोल टैक्स, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कह दी बड़ी बात

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari की ओर से दो पहिया वाहनों पर टोल टैक्स वसूलने पर जरूरी जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री की ओर से क्या कहा गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में नेशनल हाइवे पर टू व्हीलर्स को टोल टैक्स (two-wheelers toll tax) देने की जानकारी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दी जा रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से औपचारिक बयान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री की ओर से सोशल मीडिया पर इस मामले में क्या कहा गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

क्या खत्म होगी छूट?

भारत में बड़ी संख्या में लोग अपने स्कूटर और बाइक से ही लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए नेशनल हाइवे का उपयोग करते हैं। इन हाइवे पर अभी तक टू व्हीलर्स को टोल टैक्स से छूट मिलती है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि अब टोल पर मिलने वाली छूट को खत्म किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने जानकारी

ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी (Nitin Gadkari toll policy) दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ मीडिया हाऊसेस द्वारा दो-पहिया (Two wheeler) वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं हैं। दो-पहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ पत्रकारिता के लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं।

ट्वीट हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री की ओर से 26 जून 2025 को दोपहर 2.15 पर ट्वीट कर जानकारी दी गई। जिसके बाद यह ट्वीट वायरल हो रहा है। महज आधे घंटे के अंदर ही इस ट्वीट को 11 हजार से ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं।

लोग कर रहे कमेंट्स

मीडिया रिपोर्ट्स में टू व्हीलर पर टोल टैक्स वसूलने पर जब केंद्रीय मंत्री की ओर से जानकारी दी गई तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिना फैक्ट चेक किए ही इस तरह की खबर नहीं दिखानी चाहिए। तो कुछ लोग इस बात पर सफाई देने के लिए नितिन गडकरी को धन्यवाद भी कह रहे हैं।

निसान ने पेश की सबसे दमदार पैट्रोल निस्मो, मिलता है 495 HP और 700 NM टॉर्क

परिवहन विशेष न्यूज

जापानी वाहन निर्माता निसान की ओर से दुनिया के कई देशों में वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से हाल में ही प्रीमियम एसयूवी Nissan Patrol के Nismo वर्जन को पेश कर दिया है। इसमें किस तरह की खासियत को दिया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। जापान की वाहन निर्माता निसान की ओर से भारत सहित दुनिया के कई देशों में वाहनों की बिक्री की जाती है। निसान की ओर से हाल में ग्लोबल स्तर पर Nissan Patrol Nismo को पेश किया गया है। इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। किस तरह की खासियत के साथ इसे पेश किया गया है। किन देशों में इसे सबसे पहले ऑफर किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Nissan Patrol Nismo हुई पेश

निसान की ओर से नई एसयूवी के तौर पर Nissan Patrol Nismo को पेश कर दिया गया है। निर्माता की ओर से ग्लोबल स्तर पर इस एसयूवी को पेश किया गया है। जिसमें अब तक का सबसे ताकतवर इंजन दिया गया है।

कितना दमदार इंजन

निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक Nissan Patrol Nismo में 3.5 लीटर की क्षमता का वी6 इंजन दिया गया है। इसमें 3492 सीसी ट्विन टर्बो इंजन से 495 हॉर्स पावर और 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जो सामान्य पेट्रोल एसयूवी के मुकाबले 70 हॉर्स पावर ज्यादा है। इसके साथ एसयूवी में 9स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और पैडल शिफ्टर्स को दिया गया है।

कैसे हैं फीचर्स

निसान की ओर से पेट्रोल निज्मो एसयूवी में कइ बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें वी-मोशन ग्रिल, 22 इंच एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स, हाई परफॉर्मेंस टायर, ब्लैक और रेड ड्यूल इंटीरियर थीम, निज्मो बैजिंग, पैनोरमिक सनरूफ, रियर सीट्स के लिए इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ड्यूल टोन एक्सटीरियर, निज्मो ट्यून्ड ई-डैंपर्स, स्टार्ट/स्टॉप बटन, एल्यूमिनियम एक्सीलेरेटर और ब्रेक पैडल, आठ लोगों के लिए सीट्स, एयर सस्पेंशन, रॉक, सैंड, ईको, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट और मड ड्राइविंग मोड्स, 28.6 मोनोलिथ डिस्प्ले, हेड्-अप डिस्प्ले जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

किन देशों में होगी उपलब्ध

निसान की ओर से बताया गया है कि Nissan Patrol Nismo को यूएई, सऊदी अरब के साथ ही मिडल ईस्ट के सभी देशों में जुलाई 2025 से उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत में इसे लॉन्च करने को लेकर निसान की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है।

हुआवेईकी तकनीक से खत्म हो जाएगी EV की टेंशन, क्या पांच मिनट की चार्जिंग से मिलेगी 3200 KM की रेंज?

नई दिल्ली। चीन की स्मार्टफोन निर्माता Electric वाहनों के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ रही है। हाल में ही लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान कार Maextro S800 को लॉन्च करने के बाद अब कंपनी की ओर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जिससे EV सेगमेंट में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह जानकारी क्या है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Huawei ने किया बड़ा काम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुवावे की ओर से ईवी सेगमेंट के लिए बड़ी उपलबधि को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। निर्माता की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों में लगाई जाने वाली ऐसी बैटरी को तैयार किया है जो भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज की परेशानी को खत्म कर सकती है।

क्या मिली जानकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक हुवावे की ओर से ऐसी बैटरी को बनाया जा रहा है जिसे सिर्फ पांच मिनट चार्ज करने के बाद गाड़ी को 3200 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से इस सॉलिड स्टेट बैटरी के लिए पेटेंट को भी दायर किया गया है।

किस तकनीक से बनेगी बैटरी

जानकारी के मुताबिक हुवावे की सॉलिड स्टेट बैटरी को सल्फाइड आधारित तकनीक पर बनाया गया है। जिसके कारण यह लिथियम आधारित बैटरी के मुकाबले दो से तीन गुना ज्यादा ऊर्जा देती है। अगर इस तकनीक वाली बैटरी को कारों में उपयोग किया जाता है तो इससे भविष्य में EV में रेंज की परेशानी की टेंशन को खत्म किया जा सकता है।

चीन की कंपनियों के पास सबसे ज्यादा पेटेंट

ईवी सेगमेंट में चीन की कंपनियां अन्य कंपनियों के मुकाबले काफी आगे हैं। जानकारी के मुताबिक चीन की कंपनियों के पास करीब 7600 से ज्यादा सॉलिड स्टेट बैटरी पेटेंट हैं, जो दुनिया के किसी भी देश की कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं।

लोग कर रहे कमेंट्स

सोशल मीडिया पर TechExploreszone नाम के हैंडल पर यह पोस्ट किया गया है, जिस पर दुनियाभर के लोग कई कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह असंभव लगता है, लेकिन अगर यह सच है तो इससे टेस्ला जैसी कंपनियां पीछे छूट जाएंगी। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी तरह से ग्रीन मोबिलिटी को शुरू किया जा सकता है और हजारों नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं।

भारतीय शिक्षा में पुनर्विचार भाषा

विजय गर्ग

जैसा कि जर्मनी से जापान के वैश्विक उदाहरणों में मूल भाषा की शिक्षा के मूल्य की पुष्टि की गई है, यह समय है जब भारत ने अपनी बहुलता को अपनाया - एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि समग्र सीखने और राष्ट्रीय पहचान की नींव के रूप में किसी भी देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बहुत ध्यान से और उसकी सच्ची भावना से मनाया जाना चाहिए। भारत की बहुभाषी घटना हमेशा से समाज का अभिन्न अंग रही है, लेकिन भाषाओं की बहुलता की प्रकृति बहुत भिन्न है। भारत, दुनिया के सबसे अमीर भाषाई राष्ट्रों में से एक के रूप में, अपने समाज में बहुलता और विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे इसकी सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखा गया है।

शिक्षा की वैश्विक भाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रभुत्व ने बहुभाषी लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामयिक पहचान को मान्यता दी है। औपनिवेशिक दिनों के दौरान, निहित स्वार्थों के लिए अंग्रेजी सिखाई गई थी। यह माना जाता था कि ज्ञान के क्षितिज को व्यापक बनाने की गुणवत्ता है, और ग्रंथों की विविधता के कारण, यह महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए सोचा गया था, जो कि बयानबाजी के सीखने द्वारा समर्थित था।

स्वतंत्रता के बाद भी, हम मातृभाषा को एक संज्ञानात्मक और शैक्षणिक संसाधन के रूप में सराहना करने में विफल रहते हैं और भाषा-शिक्षण संसाधन के रूप में एकाधिकारवाद के हठधर्मिता में निरपेक्षता पाते हैं। अंग्रेजी ज्यादातर लोगों के लिए, मास्टर करने के लिए एक कौशल है, न कि केवल व्यक्त करने के लिए सीखने के लिए एक भाषा। अंग्रेजी, अधिकांश भाग के लिए, एक विदेशी भाषा है, लेकिन भारत में दूसरी भाषा के रूप में माना जाता है।

संचार अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रमों द्वारा किए गए अपार नुकसान - निर्माता के बजाय संचार के रिसीवर को संचार के ऑनस को स्थानांतरित करके - अपूर्ण संज्ञानात्मक प्रसंस्करण की एक अजीब स्थिति के लिए नेतृत्व किया है, या सबसे अच्छा, आंशिक समझ में । यदि हम ग्लोब को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जर्मनी, चीन और जापान जैसे कुछ प्रमुख देश, उच्चतम तकनीकी विशेषज्ञता के साथ, अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

ऐसे देशों में बच्चों की शैक्षिक प्रगति में बाधा डालने के

लिए अंग्रेजी जैसी सार्वभौमिक भाषा में शिक्षण के लिए धक्का दिखाया गया है। मानव संसाधन विकास की कुंजी शिक्षा है, और अंग्रेजी-एकमात्र नीति एक संज्ञानात्मक और शैक्षणिक संसाधन के रूप में मातृभाषा की सराहना करने में विफल रहती है।

भाषाई डकैती के एक असहाय शिकार के रूप में, स्कूली बच्चे को अपनी मातृभाषा द्वारा पेश किए गए विशाल भाषाई शस्त्रागार का उपयोग करने से समाप्त कर दिया जाता है। इससे इस तथ्य का पता चलता है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उतनी ही प्रभावी और कार्यशील है जितनी किसी अन्य प्रमुख भाषा में हो सकती है। घरेलू भाषा, स्थानीय भाषा और मातृभाषा-आधारित प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का उपयोग यह भी बताता है कि प्रत्येक भाषा अपने शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक और शैक्षिक संसाधन प्रदान कर सकती है। ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020), भाषा शिक्षा के लिए समर्पित अपने खंड में जिसे ₹बहुभाषावाद और₹ कहा जाता है

भाषा की शक्ति", शिक्षा के दायरे में भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और स्वीकार करने का प्रयास करता है।

नीति प्रभावी संचार को बढ़ावा देने, छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को आगे बढ़ाने और सांस्कृतिक जागरूकता की खेती के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भाषा के महत्व को पहचानती है। इसमें आगे कहा गया है कि जहां भी संभव हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इसके बाद, जहां भी संभव हो, घर या स्थानीय भाषा को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा।

यह आगे जोर देता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच मौजूद किसी भी अंतराल को पाटा जाए। एनईपी 2020 तीन-भाषा सूत्र को तरलता भी प्रदान करता है, क्योंकि कोई विशिष्ट भाषा नहीं है जिसे किसी भी राज्य पर लगाया जाएगा। राज्य, क्षेत्र और छात्र भी, उन तीन भाषाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जिन्हें छात्र सीखना चाहते हैं, जबकि उनमें से कम से कम दो भारत के मूल निवासी हैं - जिनमें से एक घर, स्थानीय होने की सबसे अधिक संभावना है , या क्षेत्रीय भाषा। एनईपी 2020 का उद्देश्य अपने छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके और शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग में जनशक्ति की कमी को खत्म करके भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। हाल के वर्षों में, मातृभाषा, क्षेत्रीय, स्थानीय या घरेलू भाषाओं में शिक्षा ने दुनिया भर में गंभीर ध्यान आकर्षित किया है। मातृभाषा एक शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययनों से पता चला है कि उनकी मातृभाषा में धाराप्रवाह व्यक्तियों को उन लोगों की तुलना में उच्च शैक्षिक सफलता दर होती है जो नहीं हैं।

भाषाएँ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण हैं, और किसी की मातृभाषा में एक मजबूत नींव रखने से नई भाषाओं को सीखने में सहायता मिल सकती है। दुर्भाग्य से, कई देश - विशेष रूप से वे जो उपनिवेश थे - उच्च शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में अपने उपनिवेशवादियों की भाषा का उपयोग करना जारी रखते हैं। यह अक्सर स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों और पत्रिकाओं की अनुपलब्धता के बहाने किया जाता है।

हालांकि, यह अभ्यास उन छात्रों को डालता है जो स्कूलों से आते हैं जो नुकसान में स्थानीय भाषाओं का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य, प्रौद्योगिकी और कानून जैसे विशेष क्षेत्रों में। मातृभाषा के महत्व को पहचानना और शिक्षा और व्यापक समाज में इसके निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि एक समाज के मूलभूत कौशल को विकसित किया जा सके - जैसे साक्षरता और महत्वपूर्ण सोच। बहुभाषी कार्यक्रमों में प्रारंभिक निवेश नई शिक्षण सामग्री विकसित करने की अतिरिक्त लागत के कारण अधिक प्रतीत होता है, विशेष रूप से उन भाषाओं के लिए जिन्हें मानकीकृत नहीं किया गया है या जिनके पास स्क्रिप्ट नहीं है। इसके लिए बहुभाषी कक्षा में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी।

इसके लिए एक प्रभावी मातृभाषा-आधारित शिक्षा प्रणाली के अंतिम अंत को प्राप्त करने के लिए स्थानीय भाषाओं को समृद्ध करने के लिए नए सिरे से संसाधन आवंटन और एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता होती है। संस्कृति, रीति-रिवाजों और इतिहास की निरंतरता और संचरण सुनिश्चित करने के लिए अब घर, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है। यूनेस्को भी लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा सहित बहुभाषावाद और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने के लिए तत्काल कार्रवाई कर रहा है ।

अधिक संवेदनशील और पोषित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए मातृभाषा शिक्षा को नीति विकास में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जो शिक्षार्थियों की अनूठी भाषाई और सांस्कृतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। दुर्भाग्य से, जैसा कि हर कोई एक भाषा उपयोगकर्ता है, उन्हें लगता है कि वे भाषा पर टिप्पणी कर सकते हैं - क्योंकि यह हर किसी का व्यवसाय है और किसी का व्यवसाय नहीं है।

पुस्तकों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना

विजय गर्ग

परिचयः पुस्तकें केवल सूचना के स्रोत से अधिक हैं - वे सशक्तिकरण के लिए उपकरण हैं। ग्रामीण भारत में, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच अक्सर सीमित होती है, किताबें ज्ञान, अवसर और परिवर्तन का पुल हो सकती हैं।

मुख्य उद्देश्यः

1.। साक्षरता दरों में सुधारः

सामुदायिक पुस्तकालयों और पढ़ने के कोनों की स्थापना करें।

स्थानीय भाषाओं में आयु-उपयुक्त पुस्तकों का वितरण करें।

2.। आजीवन सीखने को बढ़ावा दें:

बच्चों और वयस्कों में पढ़ने की आदतों को समान रूप से प्रोत्साहित करें।

खेती, स्वास्थ्य, अधिकार और वित्तीय साक्षरता पर किताबें पेश करें।

3.। ब्रिज डिजिटल डिवाइडः

इंटरनेट एक्सेस की कमी वाले क्षेत्रों में कम तकनीक वाले उच्च-प्रभाव वाले शैक्षिक उपकरणों के रूप में पुस्तकों का उपयोग करें।

4। सशक्त महिला और लड़कियांः

महिलाओं के स्वास्थ्य, अधिकारों और शिक्षा पर केंद्रित पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करें।

महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित पढ़ने के स्थान बनाएं।

5.। स्थानीय संस्कृति का संरक्षण और प्रचार करेंः

उन पुस्तकों को शामिल करें जो क्षेत्रीय कहानियों, लोक कथाओं और इतिहास को दर्शाती हैं। कार्यान्वयन विचारः

मोबाइल लाइब्रेरीः गांवों की यात्रा करने वाली पुस्तकों के साथ वैन या बाइक।

बुक डोनेशन ड्राइवः शहरी-से-ग्रामीण पुस्तक साझाकरण पहल।

वालंटियर्स पढ़नाः प्रशिक्षित स्थानीय या स्वयंसेवकों का दौरा करना जो पढ़ने के सत्र का संचालन करते हैं।

गैर सरकारी संगठनों और स्कूलों के साथ साझेदारीः अधिक लाभार्थियों तक पहुंचने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए।

प्रभावः

बेहतर शैक्षिक परिणाम।

जागरूकता में वृद्धि और निर्णय लेने की सूचना दी।

ग्रामीण युवाओं में अधिक आत्मविश्वास और आकांक्षाएं।

मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर समुदाय।

पढ़ाई की भाषा

विजय गर्ग

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षिक वर्ष 2025-26 से बच्चों की शुरुआती शिक्षा उनकी मातृभाषा में कराने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक शिक्षा को बुनियादी चरण माना गया है, जिसमें दूसरी कक्षा तक के बच्चे शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के लागू होने के पश्चात इस बुनियादी चरण की शुरुआत हुई है। इससे पहले की शिक्षा नीति में केंद्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कक्षा एक से पढ़ाना शुरू होता था, किंतु अब उनका सीधे पहली कक्षा में नामांकन नहीं होता। इससे पहले बच्चों को तीन वर्ष 'प्री-प्राइमरी' यानी पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद पहली कक्षा में प्रवेश मिलता है । इस तरह पांच वर्ष बुनियाद बनाने में लगते हैं, जिसमें प्री- प्राइमरी स्कूल के तीन वर्ष तथा कक्षा एक और दो के दो वर्ष । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 का प्रारूप शामिल किया गया है। दूसरी कक्षा तक पहला चरण पांच वर्ष का, तीसरी कक्षा से पांचवीं तक तीन वर्ष का दूसरा, कक्षा छह से आठ तक तीन वर्ष का तीसरा और नौवीं से बारहवीं कक्षा तक चार वर्ष का चौथा चरण है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से पहले शिक्षा नीति- 1986 लागू थी । उसमें 10 जमा 2 जमा 3 का प्रारूप था। पहली कक्षा में सीधे प्रवेश दिए जाने का उसमें प्रावधान था ।तब प्री- प्राइमरी का चरण नहीं था ।जबसे विद्यालयों में इस नए चरण की शुरुआत हुई है, तब से लगभग तीन वर्ष के बच्चे भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे हैं ।

हम जानते हैं कि ऐसे सुकोमल, मासूम और अबोध नन्हे बच्चे- बच्चियों का मन पढ़ाई में जल्दी से नहीं लगता। उनका मन घर में धमा- चौकड़ी मचाने, खेलने-कूदने, मौज- मस्ती करने में ज्यादा रमता है। कंधे पर बस्ता लटकाए विद्यालय जाते हुए उनके मन में घबराहट बनी रहती है । जब वे कक्षा में पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें शिक्षक उनकी मातृभाषा की जगह अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हैं, तब वे परेशान हो जाते हैं । जो पढ़ाया जाता है, उसे वे समझ नहीं पाते । जब उन्हें समझ ही नहीं आएगा, तो वे नया सीखेंगे भी कैसे। ऐसे में बच्चों की मनोस्थिति, उनकी सोचने-समझने व ग्रहण करने की सामर्थ्य और सीमाओं का नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरा ध्यान रखा गया है। उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी की जगह उनकी मातृभाषा रखने का व्यावहारिक और सराहनीय निर्णय लिया गया है ।

वर्तमान में पूरे देश में तीस हजार से अधिक विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं और इनमें से अधिकांश में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी है। नन्हे बच्चों को सबसे मुश्किल अंकगणित लगता है, लेकिन जब वे अंकों की पहचान, उनकी गिनती, जोड़ना, घटाना आदि अपनी मातृभाषा में सीखेंगे - पढ़ेंगे, तब उनके मन से गणित का भय दूर हो जाएगा और उनमें गणित सीखने की रुचि जागृत होगी ।राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा, क्षेत्रीय या राज्य भाषा में कराने पर जोर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई का विकल्प होना चाहिए, ताकि वे अंग्रेजी भाषा के दबाव से मुक्त रह कर अपनी रुचि से पढ़ सकें ।

विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, वे मातृभाषा भी हैं। मां की बराबरी मां के अलावा कोई नहीं कर सकता, वैसे ही मातृभाषा की बराबरी भी कोई दूसरी भाषा नहीं कर सकती । केंद्रीय विद्यालयों में आरंभिक पढ़ाई मातृभाषा में कराए जाने का निर्णय निश्चित रूप से विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए लाभकारी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने वाला है। मगर अंग्रेजी मोह में डूबे अभिभावक रुकावट डाल सकते हैं, इसलिए उन्हें समझाना जरूरी है। नगरों - महानगरों से लेकर गांव-ढाणियों तक अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल फैल गए हैं। अधिकतर अभिभावकों की यह मानसिकता बनी हुई है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ा कर ही वे अपने अधूरे सपने बच्चों के माध्यम पूरे कर सकेंगे ।हिंदी या मातृभाषा के माध्यम से पढ़ेंगे तो वे पिछड़ जाएंगे।

अभिभावकों को समझना होगा कि आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से बच्चे सहजता से सीख लेंगे। पढ़ते, लिखते और सीखते उन्हें आनंद की अनुभूति होगी, मानसिक परेशानी नहीं। दरअसल, अंग्रेजी उनके लिए पराई भाषा है, मातृभाषा अपनी भाषा । यह ठीक है कि बच्चों को अंग्रेजी ही क्यों, अन्य भाषाएं भी सीखने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जितनी भाषाओं से उनका सरोकार बनेगा, उतने ही वे मानसिक और शैक्षणिक स्तर पर समृद्ध होंगे। पर, मातृभाषा में आरंभिक पढ़ाई कराने का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा की उपेक्षा करना नहीं, वरन बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना है। अभिभावकों को मातृभाषा में पढ़ाई के महत्त्व को लेकर जागरूक करने के साथ ही अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तभी बच्चे शुरुआती पढ़ाई अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे और आगे चलकर अपने भविष्य को संवार सकेंगे ।

उच्च शिक्षा के लिए उनके संक्रमण के लिए कोचिंग केंद्रों पर छात्रों की निर्भरता कम करें

विजय गर्ग

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चिंताओं पर विचार करने के लिए एक ग्यारह सदस्यीय पैनल का गठन किया है और उच्च शिक्षा के लिए उनके संक्रमण के लिए इन केंद्रों पर छात्रों की निर्भरता को कम करने के उपायों का सुझाव दिया है।

उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की अध्यक्षता करने के लिए, पैनल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के अध्यक्ष, स्कूल के विभागों के संयुक्त सचिव और उच्च शिक्षा, और तीन IIT - मद्रास, त्रिची और कानपुर के प्रतिनिधि भी शामिल हैं - साथ ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)।

पैनल में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एक निजी स्कूल के प्रिंसिपलों में से नामांकित होने वाले तीन सदस्य भी शामिल होंगे।

बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा एक्सेस किए गए आदेश के अनुसार, पैनल औपचारिक स्कूली शिक्षा की लागत पर पूर्णकालिक कोचिंग को प्रोत्साहित करने में डमी स्कूलों के उद्भव और उनकी भूमिका के पीछे के कारणों की जांच करेगा, और इस मुद्दे को कम करने के तरीके सुझाएगा।

यह सीबीएसई के बाद आता है, मार्च 2025 में, डमी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों को कक्षा 12 की परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने से रोक दिया। डमी स्कूल ऐसे संस्थान हैं जहां छात्रों को आधिकारिक तौर पर नामांकित किया जाता है लेकिन नियमित कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

ये स्कूल अक्सर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) जैसी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ जुड़े होते हैं।

इस पहल को देश में स्कूली शिक्षा को फिर से शुरू करने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम बताते हुए डीएलएफ फाउंडेशन स्कूल और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में शिक्षा, नवाचार और प्रशिक्षण की चेयरपर्सन डॉ अमीता मुल्ला वाटल ने कहा कि इस कदम से स्कूल प्रणालियों को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है जो अप्रासंगिक हो गए हैं-विशेष रूप से वरिष्ठ स्तर पर-डमी स्कूलों के उदय के कारण ।

समिति वर्तमान स्कूली शिक्षा प्रणाली में अंतराल की भी जांच करेगी, विशेष रूप से महत्वपूर्ण सोच और तार्किक तर्क पर सीमित ध्यान और रटने सीखने की व्यापकता।

डॉ। वाटल ने कहा कि स्कूल और कोचिंग पाठ्यक्रम के बीच गलतफहमी पर चर्चा करने की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि रटने सीखने की एक परीक्षा केंद्रित प्रणाली छात्रों को अपने विषयों में अकादमिक गहराई विकसित करने में मदद नहीं कर सकती है।

जोशी समिति स्कूली शिक्षा के संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रभावशीलता और निष्पक्षता और कोचिंग उद्योग के विकास में उनकी भूमिका का अध्ययन करेगी।

कई कैरियर मार्गों और कैरियर परामर्श के बारे में छात्रों और अभिभावकों के बीच जागरूकता स्तरों का मूल्यांकन करने का भी काम किया गया है।

पैनल अतिरिक्त रूप से विज्ञापन प्रथाओं की समीक्षा करेगा, जिसमें भ्रामक दावों का उपयोग और चयनात्मक सफलता की कहानियों को बढ़ावा देना शामिल है, और इस मुद्दे को संबोधित करने के उपायों का सुझाव देगा।

यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए पिछले साल दिशानिर्देश जारी करने के बाद आया है, अतिरंजित सफलता दरों, भ्रामक दावों और कोचिंग संस्थानों द्वारा अक्सर लगाए गए अनुचित अनुबंधों के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में।

भारत क्यों नहीं करता रेयर अर्थ एलीमेंट्स का उत्पादन, जबकि जमीन के नीचे दबा है भंडार

विजय गर्ग

रेयर अर्थ एलीमेंट्स (रेयर अर्थ एलीमेंट्स – आरईई) आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया के लिए उतने ही जरूरी हैं, जितना इंसान के लिए अनाज. इन्हें हिन्दी में 'दुर्लभ पृथ्वी तत्व' कहा जाता है. ये तत्व इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर मोबाइल फोन, रक्षा उपकरण, और पवन टरबाइन जैसी हाई-टेक चीजों में इस्तेमाल होते हैं. यदि इनका इस्तेमाल न किया जाए तो ये बस उपकरण बेकार हैं. और चीन इस क्षेत्र में 'बादशाह' है और एकछत्र राज करता है. वह दुनिया के 70 फीसदी दुर्लभ तत्वों का खनन और 90 फीसदी रिफाइनिंग करता है. यानी पूरी दुनिया इस मामले में चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है.

भारत क्यों नहीं करता रेयर अर्थ एलीमेंट्स का उत्पादन? जबकि जमीन में बड़ा भंडार

चीन आज जिस स्थिति में है, वहां वह एकाएक नहीं पहुंचा है. 1990 के बाद से उसने इन तत्वों को रणनीतिक रूप से जरूरी माना और अपने नियमों, टेक्नोलॉजी और नीतियों को उसी हिसाब से बदला. चीन के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा आरईई भंडार हैं और वहां सस्ती मजदूरी और ढीले पर्यावरण नियमों की वजह से उत्पादन बहुत सस्ता होता है. चीन के पास सस्ती बिजली उपलब्ध है, जो रिफाइनिंग जैसे ऊर्जा-गहन कामों में मदद करती है. इसके साथ ही, चीन ने टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल कर ली है. वहां के 39 विश्वविद्यालयों में इस बारे में पढ़ाई होती है. इसके मुकाबले दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में एक भी कोर्स नहीं है.

रेयर अर्थ मैग्नेट, रेयर अर्थ एलीमेंट्स, चीन बनाम पूरी दुनिया, भारत में रेयर अर्थ एलीमेंट्स के भंडार

चीन ने कई बार इन खनिजों का राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया है. 2010 में उसने जापान को निर्यात रोक दिया था, जिससे दुनिया को समझ आ गया कि ये खनिज केवल तकनीकी चीज नहीं है, वे रणनीतिक हथियार भी बन सकते हैं.

भारत में क्या हैं मुश्किलें

दूसरी तरफ भारत और अमेरिका जैसे देशों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. हालांकि इनके पास भी अच्छे भंडार हैं, लेकिन इन्हें निकालना और रिफाइन करना इतना आसान नहीं है. इन तत्वों को जमीन से निकालने में रेडियोधर्मी तत्वों से भी जूझना पड़ता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को खतरा होता है. भारत और अमेरिका में पर्यावरणीय नियम कड़े हैं, जिससे प्रोजेक्ट महंगे हो जाते हैं.

प्रोसेसिंग के लिए भारत भी चीन पर निर्भर

भारत के पास 6.9 मिलियन टन आरईई हैं, लेकिन 2024 में उसने केवल 2,900 टन का ही उत्पादन किया, यानी दुनिया का केवल 1 फीसदी. केरल के कोच्चि में मोनाजाइट रेत से ये तत्व निकलते हैं, लेकिन वहां खनन और प्रोसेसिंग की सुविधा बहुत सीमित है. इसके अलावा स्थानीय लोगों का विरोध और पर्यावरणीय चिंता भी बड़े कारण हैं. भारत की निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में बहुत कम सक्रिय हैं. ज़्यादातर कच्चा माल चीन भेजा जाता है, जहां उसकी रिफाइनिंग होती है. इसी कारण भारत 99 फीसदी मैग्नेट और बैटरियां चीन से मंगवाता है.

ये भी पढ़ें – रेयर अर्थः भारतीय कंपनियों की फाइलों पर कुंडली मारकर बैठा है चीन का मंत्रालय

चीन की निर्भरता की वजह से भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेक्टर पर भी असर पड़ रहा है. कई भारतीय कंपनियां जैसे मारुति और बजाज को अब पूरी मोटर असेंबली विदेश से मंगवानी पड़ रही है, जिससे लागत बढ़ रही है. भारत सरकार ने अब इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं. 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में चीन पर निर्भरता को खतरे के रूप में बताया गया है और सरकार निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन नतीजे आने में अभी समय लगेगा.

अमेरिका में भी काफी कम उत्पादन

अमेरिका में भी हालात ऐसे ही हैं. वहां केवल माउंटेन पास नाम की एक खदान है जो 2024 में 45,000 टन का उत्पादन कर सकी. फिर भी अमेरिका अपनी जरूरत का 70% से ज्यादा हिस्सा चीन से ही मंगवाता है. अमेरिका पहले इस क्षेत्र में आगे था, लेकिन चीन की सस्ती लागत और ढीले पर्यावरण नियमों ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया. अमेरिका के पास अब भी रिफाइनिंग की पर्याप्त सुविधा नहीं है और टेक्नोलॉजी की भी कमी है. कुछ नए रिफाइनिंग प्लांट्स शुरू जरूर हो रहे हैं, जैसे टेक्सास में एमपी मैटेरियल्स की सुविधा, लेकिन उसका उत्पादन चीन के मुकाबले बहुत कम होगा.

टेक्नोलॉजी भी बेच नहीं रहा चीन

चीन ने तो अब यहां तक कर दिया है कि वह अपनी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को न बेचे, जिससे और देशों की तरक्की और रुक जाए. अमेरिका और भारत दोनों को अब अपने देश में निवेश बढ़ाने, टेक्नोलॉजी लाने और पर्यावरणीय नियमों का बेहतर समाधान निकालने की जरूरत है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देशों से साझेदारी और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना भी जरूरी है.

अंतरिक्ष से भारत की हुंकार: शुभांशु शुक्ला की अमर उड़ान

[अंतरिक्ष में लहराता हंस: विज्ञान और विरासत की संगम-यात्रा]

जब एक भारतीय ने सितारों को छू लिया, तो वह पल केवल अंतरिक्ष की यात्रा नहीं था—वह 140 करोड़ दिलों की धड़कनों का उत्सव था, भारत की आत्मा का उद्घोष था, और हमारी सांस्कृतिक विरासत का ब्रह्मांड में लहराता तिरंगा था। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने जब ड्रैगन कैप्सूल से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की ओर कदम बढ़ाया, तो वह केवल एक अंतरिक्ष यात्री की उड़ान नहीं थी—वह भारत के सपनों, संकल्प और वैज्ञानिक शक्ति की अनंत यात्रा थी। यह वह क्षण था जब भारत ने न केवल धरती की सीमाएं लांघीं, बल्कि सितारों के पार अपनी पहचान को अमर कर दिया।

25 जून 2025 को, भारतीय समयानुसार दोपहर 12:01 बजे, फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स का फाल्कन-9 रॉकेट आकाश को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार थे भारतीय वायुसेना के शुभांशु शुक्ला, जो एक्सिओम-4 मिशन के पायलट की भूमिका में थे। उनके साथ थे कमांडर पैगी व्हिटसन (पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री, अमेरिका), मिशन विशेषज्ञ स्लावोश उज्नांस्की-विस्निव्स्की (पोलैंड), और तिबोर कपु (हंगरी)। यह मिशन नासा, एक्सिओम स्पेस और स्पेसएक्स की साझेदारी का प्रतीक है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का समर्थन प्राप्त है।

लॉन्च के महज 10 मिनट बाद, शुभांशु और उनकी टीम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। 28 घंटे की रोमांचक यात्रा के बाद, ड्रैगन कैप्सूल 26 जून 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे आईएसएस से डॉक करने वाला है। यह 14-दिवसीय मिशन 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों का मंच है, जिनमें सात इसरो द्वारा डिजाइन किए गए हैं। ये प्रयोग भारत की वैज्ञानिक प्रगति को विश्व मंच पर चमकाने का अवसर हैं, जो न केवल तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि भारत के भविष्य के अंतरिक्ष सपनों का आधार भी है।

शुभांशु की यह यात्रा 1984 में राकेश शर्मा की ऐतिहासिक सोवियत सैल्यूट-7 मिशन के बाद भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान में शानदार वापसी है। 41 साल बाद, शुभांशु आईएसएस पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं, जो भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम स्याही से लिखा जाएगा। यह केवल एक व्यक्ति की उड़ान नहीं, बल्कि भारत की उस जिजीविषा का प्रतीक है, जो सीमाओं को तोड़कर अनंत की ओर बढ़ रही है।

इस मिशन की आत्मा भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है।

शुभांशु ने अपने साथ एक सॉफ्ट टॉय हंस लिया, जिसे भारतीय शास्त्रों में ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना जाता है। यह हंस अंतरिक्ष की अनंतता में तैर रहा है, जैसे भारत की सांस्कृतिक विरासत सितारों के बीच अपनी चमक बिखेर रही हो। लॉन्च के दौरान, उनके कंधे पर लहराता तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं था—वह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, गर्व और एकता का प्रतीक था। यह तिरंगा गर्व से कह रहा था कि यह उड़ान केवल शुभांशु की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है, जो खेतों से लेकर प्रयोगशालाओं तक, सपनों को हकीकत में बदल रहा है।

शुभांशु ने भारतीय खान-पान को भी अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आम का रस, गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा उनके साथ गए, जो वे अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साझा करेंगे। इसके अलावा, वे माइक्रोग्रैविटी में योग करने की योजना बना रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति का वैश्विक मंच पर एक अनूठा प्रदर्शन होगा। यह वह क्षण है जब परंपरा और प्रौद्योगिकी ने एक-दूसरे का हाथ थामा, और भारत ने साबित कर दिया कि वह न केवल विज्ञान में, बल्कि संस्कृति में भी अग्रणी है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है। शुभांशु सात भारतीय प्रयोग करेंगे, जिनमें माइक्रोग्रैविटी में मूंग और मेथी के अंकुरण का अध्ययन और मांसपेशियों की हानि का विश्लेषण शामिल है। ये प्रयोग भारत और अमेरिका की साझेदारी का परिणाम हैं और इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करेंगे। गगनयान, जो 2026 में लॉन्च होने वाला है, भारत का पहला स्वदेशी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। शुभांशु, जो इसके लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं, इस मिशन के लिए अमूल्य अनुभव ला रहे हैं। कुल 60 से अधिक प्रयोग, जिनमें सामग्री विज्ञान, जैविक अनुसंधान और मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोग्रैविटी के प्रभाव शामिल हैं, भारत के भविष्य के मिशनों—जैसे 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने—के लिए नींव रखेंगे।

यह यात्रा केवल अंतरिक्ष तक की उड़ान नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव है। यह वह क्षण है जब भारत ने साबित कर दिया कि वह न केवल धरती पर, बल्कि सितारों के बीच भी अपनी छाप छोड़ सकता है। शुभांशु की उड़ान लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो अब सपने देखने से आगे बढ़कर उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत रखते हैं। यह वह दस्तक है जो ब्रह्मांड के दरवाजे पर भारत की उपस्थिति को अमर कर रही है—न केवल एक यात्री के रूप में, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में।

जब शुभांशु का ड्रैगन कैप्सूल सितारों के बीच तैर रहा है, तो वह केवल एक अंतरिक्ष यान नहीं है—वह भारत के सपनों का वह पंख है, जो अनंत आकाश में उड़ रहा है। यह न कोई अंत है, न कोई पड़ाव। यह तो एक नई शुरुआत है—उस भारत की, जो अब ब्रह्मांड की गहराइयों में अपनी कहानी लिख रहा है, और जिसकी गूंज सितारों से सितारों तक अनंत काल तक गूंजेगी। यह भारत का वह उद्घोष है, जो कहता है: "हम आए हैं, और हम रहेंगे—धरती पर, आकाश में, और सितारों के पार!"

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

लैंगिक समानता की राह में भारत की गिरावट: एक चिंताजनक संकेत

विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम) की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट २०२४ में भारत को 148 देशों में 131वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। यह न केवल दो पायदान की गिरावट है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में छुपी उस असमानता का पर्दाफाश भी करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब पूरी दुनिया लैंगिक असमानता को घटाने में धीमी किंतु स्थिर प्रगति कर रही है, तब भारत का पिछड़ना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि नीति, सोच और संस्थागत व्यवस्था की विफलता का प्रतिबिंब है।

वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक (ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स), जिसे २००६ में शुरू किया गया था, चार प्रमुख क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को मापता है—आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण। भारत का कुल स्कोर 64.1% है, जो वैश्विक औसत 68.5% से काफी कम है। यही नहीं, दक्षिण एशिया में भी भारत बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे पड़ोसी देशों से पीछे है।

आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में भारत ने मामूली सुधार किया है, लेकिन महिलाओं की श्रम भागीदारी दर अभी भी 45.9% पर अटकी हुई है। महिलाएँ मुख्यत: देखभाल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कम वेतन वाले क्षेत्रों में केंद्रित हैं। घरेलू और अवैतनिक श्रम, जो देश की असंगठित अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अभी तक किसी राष्ट्रीय लेखांकन में शामिल नहीं किया गया है।

महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान कार्य के लिए १०–३०% कम वेतन प्राप्त होता है। यह आर्थिक असमानता केवल आँकड़ों की नहीं, सोच की समस्या है।

शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति तो हुई है, परंतु महिला साक्षरता दर अभी भी लगभग 70% है, जो वैश्विक औसत 87% से बहुत कम है। उच्च शिक्षा, विशेषकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (एसटीईएम) क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों और निम्नवर्गीय परिवारों की लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने वाली सामाजिक बाधाएँ—जैसे बाल विवाह, रुढ़िवादी सोच और विद्यालयों की दूरी—अब भी मौजूद हैं।

स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा के पैमाने पर भी भारत पिछड़ा हुआ है। जन्म के समय लिंग अनुपात अब भी ९२९ लड़कियाँ प्रति 1000 लड़कों के आसपास है। मातृत्व से जुड़ी समस्याएँ, कुपोषण, रक्ताल्पता (एनीमिया), और प्रसवकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। घर की चारदीवारी में महिलाओं की सेहत को प्राथमिकता न मिलना हमारी पारिवारिक व्यवस्था की कमजोरी है।

राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व घटकर 13.8% रह गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल 5.6% महिलाएँ हैं। यह तब और विडंबनापूर्ण हो जाता है जब हम जानते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक २०२३ पारित हो चुका है, परंतु जनगणना और निर्वाचन क्षेत्र पुन:निर्धारण की प्रक्रिया के विलंब के कारण उसका क्रियान्वयन अटका हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल कानून पारित करना पर्याप्त नहीं, उन्हें लागू करने की इच्छाशक्ति भी आवश्यक है।

भारत को अपने पड़ोसी देशों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश जैसे देश ने सूक्ष्म वित्त, महिला शिक्षा प्रोत्साहन, और निरंतर राजनीतिक भागीदारी जैसे उपायों से सकारात्मक सुधार किए हैं। नेपाल में संविधान द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई निम्न आय वाले देशों ने धनी देशों की तुलना में लैंगिक समानता में अधिक तेजी से प्रगति की है, जो यह दर्शाता है कि बदलाव के लिए धन नहीं, दृढ़ नीयत चाहिए।

लैंगिक समानता केवल एक सामाजिक उद्देश्य नहीं, भारत की आर्थिक प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। मैकिंज़ी ग्लोबल संस्थान का अनुमान है कि यदि भारत कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाता है, तो २०२५ तक अपनी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 700 अरब डॉलर तक की वृद्धि कर सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन में महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक परिणाम भी अधिक न्यायसंगत और समावेशी होते हैं। भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता तभी सार्थक होगी, जब उसमें महिलाओं की पूरी और समान भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

किन्तु चुनौतियाँ गहरी हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्य, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षा की कमी, डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुँच और नीतियों के क्रियान्वयन में ढिलाई—ये सभी मिलकर लैंगिक असमानता को टिकाऊ बना रहे हैं।

अब समय आ गया है कि भारत केवल योजना बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें ज़मीन पर उतारे। महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने हेतु जनगणना और निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। घरेलू और अवैतनिक श्रम को राष्ट्रीय आर्थिक लेखा-जोखा में शामिल कर उसे सम्मान और सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। महिलाओं के लिए लचीले और सुरक्षित कार्यस्थलों की व्यवस्था की जाए, विशेषकर ग्रामीण एवं अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में।

निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों में महिला निदेशक की अनिवार्यता हो।

विज्ञान, राजनीति और उद्यमिता में महिलाओं के लिए परामर्श (मेंटॉरशिप) कार्यक्रम चलाए जाएँ। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए महिलाओं को सस्ते मोबाइल व इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को पंचायत स्तर तक पहुँचाया जाए।

हर योजना और सर्वेक्षण में लैंगिक रूप से अलग आँकड़े संकलित करना अनिवार्य हो ताकि राज्य और जिले स्तर पर प्रगति की निगरानी की जा सके और नीति निर्माण अधिक लक्षित हो सके।

भारत की लैंगिक समानता में यह गिरावट केवल एक आँकड़ा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है—कि हमने विकास की दौड़ में आधी आबादी को पीछे छोड़ दिया है। यह भूल केवल सामाजिक न्याय की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि की भी कीमत वसूलती है।

समानता की राह लंबी है, पर असंभव नहीं। नीति बन चुकी है, दिशा स्पष्ट है, अब आवश्यकता है राजनीतिक संकल्प, सामाजिक सहमति और संस्थागत क्रियान्वयन की। जब तक भारत अपनी आधी आबादी को बराबरी का स्थान नहीं देगा, तब तक "विकसित राष्ट्र" का सपना अधूरा रहेगा।

(प्रियंका सौरभ एक स्वतंत्र स्तंभकार, कवयित्री और सामाजिक विषयों पर मुखर लेखिका हैं। वे विशेष रूप से महिला अधिकार, शिक्षा और ग्रामीण भारत की आवाज़ को अपने लेखन में प्राथमिकता देती हैं।)

–प्रियंका सौरभ

सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2026 से वर्ष में दो बार होगी- सप्लीमेंट्री खत्म-पहली परीक्षा फरवरी में कंपलसरी, दूसरी मई में ऑप्शनल-अप्रैल जून में नतीजे

परीक्षा के नए पैटर्न में छात्रों को अंकों में बेहतर सुधार का यह मौका करियर में मील का पत्थर साबित होगा

सीबीएसई 10वीं का नया पैटर्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुरूप,परीक्षाओं में कम तनावपूर्ण माहौल व छात्रों को सीखने का बेहतर मौके देना है

–एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर पूरी दुनिया के मंझे हुएशिक्षाविदों बुद्धिजीवियों व शिक्षा के क्षेत्र में विशेष विश्लेषणात्मक भूमिका रखने वालों की पूरी नजर गढ़ी हुई है, क्योंकि इस नई राष्ट्रीय नीति 2020 में अनेकों ऐसे अनुशंसित नियम व मौके हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत की पीढ़ीयों में मील का पत्थर साबित होंगे। इसके पूर्व हमने देखे कि इंजीनियरिंग सहित अनेको कोर्स अपनी मातृभाषा में करने का सटीक सिस्टम लागू किया गया है, जो इस एनईपी 2020 का ही हिस्सा है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के सभी राज्यों ने भी तुरंत लागू करना चाहिए क्योंकि इस शिक्षा नीति को अपनाने से जोजनरेशन निकलेगी वह पारिस्थितिकीजन्य विश्लेषण कर नई प्रौद्योगिकी वह नीति से आगे बढ़ाने वाली होगी।आज इस विषय पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीबीएसई के एग्जामिनर कंट्रोलर ने बुधवार दिनांक 25 जून 2025 शाम को प्रेस में बताया कि दसवीं की परीक्षा अब सत्र 2025-2026 से वर्ष में दो बार होगी, व उसका पूरा विवरण बताए जो हम नीचे पैराग्राफ में चर्चा करेंगे।चूँकि इस नए पैटर्न से छात्रों को अंकों में बेहतर सुधार करने का मौका मिलेगा जो उनके करियर में मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे सीबीएसई 10वीं बोर्ड का नया पैटर्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुरूप परीक्षाओं को कम तनावपूर्ण व छात्रों को सीखने का बेहतर मौका देना है।

साथियों बात अगर हम सत्र 2025-26 से सीबीएसई 10वीं की परीक्षा पैटर्न में चेंज की करें तो,अगर हम या हमारे बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर हमारे लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के तरीके में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है, अब छात्रों को परीक्षा में साल में दो बार बैठने का मौका मिलेगा, यानी अगर कोई छात्र अपने पहले प्रयास के अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह दूसरी परीक्षा में बैठ सकता है, इसका उद्देश्य छात्रों पर से दबाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का दूसरा मौका देना है।सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक ने दी जानकारी दीं उन्होंने कहा, ''पहला चरण फरवरी में और दूसरा मई में आयोजित किया जाएगा, दोनों चरणों के परिणाम क्रमशः अप्रैल और जून में घोषित

किए जाएंगे"इससे छात्रों को एक ही शैक्षणिक सत्र में दो अवसर मिलेंगे और वे समय पर अपने करियर और आगे की पढ़ाई के लिए निर्णय ले सकेंगे।उन्होंने आगे कहा, ''छात्रों के लिए पहले चरण में शामिल होना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरा चरण वैकल्पिक होगा, छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का मौका मिल सकेगा, इसका मतलब यह है कि छात्र केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दोबारा देंगे, जिनमें वे अपनी पहली कोशिश से संतुष्ट नहीं हैं "तय मानदंडों के अनुसार, शीतकाल में बंद रहने वाले स्कूलों के दसवीं कक्षा के छात्रों को किसी भी चरण में उपस्थित होने का विकल्प मिलेगा. इसके अनुसार, शैक्षणिक सत्र के दौरान आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा, यह बदलाव परीक्षा प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है, सीबीएसई ने फरवरी में मसौदा मानदंडों की घोषणा की थी और हितधारकों की प्रतिक्रिया मांगी गई थी, नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के मुताबिक, बोर्ड परीक्षाओं की ''उच्च अपेक्षा" वाले पहलू को खत्म करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी शैक्षणिक वर्ष के दौरान दो मौकों पर परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।सीबीएसई का यह नया पैटर्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। नीति का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं को कम तनावपूर्ण बनाना और छात्रों को सीखने के बेहतर मौके देना है,सीबीएसई ने इस बदलाव से पहले फरवरी 2025 में ड्राफ्ट नियम जारी कर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे थे,इन सुझावों के आधार पर ही यह नया पैटर्न तैयार किया गया है।सीबीएसई का यह नया फैसला बोर्ड परीक्षा को ज्यादा लचीला और छात्र- केंद्रित बनाता है, अब छात्र अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दो मौके पा सकेंगे, जिससे परीक्षा का तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कक्षा 10 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा के पहले चरण में उपस्थित होना अनिवार्य, दूसरा चरण वैकल्पिक रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा।इस फैसले के बाद छात्रों को अपने अंकों में सुधार का मौका मिल पाएगा। यदि किसी छात्र के अंक पहले चरण में कम रह जाते हैं, तो वह दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन करके सुधार कर सकेगा, यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में अनुशंसित एक कदम है।

साथियों बात अगर हम 10वीं सीबीएसई के इस चेंज पैटर्न को गहराई से समझने की करें तो, नए एग्जाम पैटर्न की 3 अहम बातें, परीक्षा यानी ऑप्शनल एग्जाम में छात्रों को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की इजाजत दी जाएगी।विंटर बाउंड स्कूलों (सर्दियों में बंद रहने वाले स्कूल) के छात्रों को दोनों परीक्षाओं में से किसी में भी बैठने की इजाजत होगी। अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं हुआ है, तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि पहले और दूसरे चरण की परीक्षाओं में सेलेबस भी एक ही रहेगा और पूर्ण पाठ्यक्रम शामिल होगा, इसके साथ ही जो स्टूडेंट दोनों परीक्षा में हिस्सा लेंगे, उनके परीक्षा केंद्र एक ही होंगे,(1) अगर एग्जाम फीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही दोनों परीक्षाओं की फीस जमा करनी होगी। (2) सीबीएसई दूसरे एग्जाम के जरिए उन स्टूडेंट्स को मौका देना चाहता है, जो एक बार परीक्षा के बाद अपने परिणामों में सुधार करना चाहते हैं (3) अगर कोई स्टूडेंट साल की दोनों परीक्षाओं में हिस्सा लेता है तो उसके उन नंबरों को फाइनल माना जाएगा, जो ज्यादा होंगे, अगर किसी के पहले एग्जाम में ज्यादा नंबर आते हैं और दूसरे एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो उसके पहले चरण की परीक्षा के नंबर को फाइनल माना जा सकता है। बता दें कि स्टूडेंट्स तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की अनुमति दी जाएगी, अगर कोई स्टूडेंट पहली परीक्षा में 3 या 3 से ज्यादा विषयों में शामिल नहीं हुआ है तो उसे दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा।सीबीएसई की ओर से फरवरी में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसमें कहा गया था कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच आयोजित हो सकती है और दूसरे चरण की परीक्षाएं 5 से 20 मई के आयोजित होंगी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2026 से वर्ष में दो बार होगी- सप्लीमेंट्री खत्म-पहली परीक्षा फरवरी में कंपलसरी, दूसरी मई में ऑप्शनल-अप्रैल जून में नतीजे,परीक्षा के नए पैटर्न में छात्रों को अंकों में बेहतर सुधार का यह मौका करियर में मील का पत्थर साबित होगा।सीबीएसई 10वीं का नया पैटर्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुरूप,परीक्षाओं में कम तनावपूर्ण माहौल व छात्रों को सीखने का बेहतर मौके देना है।

कोई तो सीवरेज साफ-सफाई कर्मियों के बारे में सोचें।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल-2025 के अनुसार भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कुछ समय पहले इसकी पुष्टि करते हुए बताया था कि भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) अब 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है, यह हम सभी को गौरवान्वित महसूस कराता है, लेकिन विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का तमग़ा हासिल करने के बाद भी जब हमारे यहां से सीवर की सफाई करते लोगों की मौत की खबरें आती हैं, तो यह हमें बहुत विचलित करतीं हैं। वाकई यह बहुत ही दुखद है कि आए दिन हमें मीडिया की सुर्खियों में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मजदूरों की मौत के मामले पढ़ने सुनने को मिलते रहते हैं। हाल ही में यूपी के वृंदावन में सीवर सफाई कर रहे दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह घटना केशव धाम पुलिस चौकी के निकट स्थित एक पेट्रोल पंप के पास गेस्टहाउस के सीवर की सफाई के दौरान हुई। दोनों श्रमिक सीवर चैंबर में जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। हमारे देश में सीवरेज की सफाई का काम अक्सर समाज का सबसे कमजोर व गरीब वर्ग करता है, ऐसे में क्या इन सबसे कमजोर व गरीब वर्ग की चिंता हम सभी को तथा सरकार को नहीं करनी चाहिए, यह प्रश्न अपने आप में एक यक्ष व ज्वलंत प्रश्न है। पिछले साल एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक में छपी एक खबर के अनुसार सफाई के काम में लगे 38,000 कर्मचारियों में से 91.9% कर्मचारी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों से हैं। बहरहाल,कहना ग़लत नहीं होगा कि हमारे देश में सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों के आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं। यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल के अनुसार पिछले 31 सालों में 1248 लोगों की मौत हुई है और इनमें से सबसे ज्यादा मौतें तमिलनाडु (253), गुजरात (183), उत्तर प्रदेश (133), और दिल्ली (116) में हुई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2023 के बीच 377 लोगों की मौत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई है।जुलाई 2022 में लोकसभा में पेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पांच सालों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 347 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 40 प्रतिशत मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुईं।यदि हम यहां पर सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों की बात करें तो इनमें क्रमशः मैनुअल सीवर सफाई(सीवर और सेप्टिक टैंकों में जहरीली गैसों के कारण),सुरक्षा उपकरणों का अभाव(सीवर की सफाई के दौरान सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना),लापरवाही(ठेकेदारों और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही),सीवर सफाई के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना, तथा सीवर सफाई के खतरों के बारे में जागरूकता की कमी हैं। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि देश में साल 1993 में पहली बार सीवरों की मैनुअल सफाई और मैला ढोने की प्रथा पर बैन लगाया गया था तथा इसके 20 साल बाद मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट, 2013 के जरिए इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी आए दिन सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मजदूरों की मौत के मामले सामने आते रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना और दुख की बात भला और क्या हो सकती है ? आज हम एआइ चैटबाट (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के आधुनिक युग में जी रहे हैं।देश के पास चांद तक पहुंचने की तकनीक उपलब्ध है, लेकिन सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए आज भी मशीनों , तकनीक और सुरक्षा उपकरणों की कमी है। शायद यही वजह है कि मजदूर इन जहरीली गैस वाले टैंकरों में खुद उतरकर मैन्नूयुअल रूप इन सीवरेज की सफाई करते हैं।हैरानी की बात तो यह है कि हमारे देश में आज मैनुअल सीवर की सफाई पर कानूनन बैन है, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं।कानून के मुताबिक, अगर मजदूरों को परिस्थितिवश अगर सीवर में उतरना पड़ता है को उनको 27 दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है, लेकिन इन दिशा-निर्देशों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और मजदूरों को सीधा मौत में उतार दिया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या एजेंसी एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी व्यक्ति को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए नियुक्त करती है, उसे अधिनियम की धारा 8 के तहत दो साल तक की कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बहुत बार जब सीवरेज में मौत के मामले सामने आते हैं तो ऐसे मामलों के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन की ओर से इस संबंध में मामला दर्ज किए जाने और मुआवजा देने के आश्वासन जैसी औपचारिकताएं पूरी की जातीं हैं, लेकिन उससे पहले कुछ होता नहीं है,यह बहुत ही अफसोसजनक है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज जरूरत इस बात की है,हम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति कर चुके हैं,अब पारंपरिक तरीकों से सीवरेज की साफ-सफाई पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। फिर भी यदि किसी कारणवश इन सीवरेज की साफ-सफाई के लिए मजदूरों को इनमें उतरना ही पड़ता है तो सीवर सफाई के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है, ताकि मौत के आंकड़ों पर अंकुश लगाया जा सके। वास्तव में सीवर में उतरने वाले व्यक्तियों को गैस डिटेक्टर, सुरक्षात्मक कपड़े (जैसे कि दस्ताने, जूते, और सुरक्षात्मक सूट), और श्वसन उपकरण (जैसे कि गैस मास्क या एयर-सप्लाई रेस्पिरेटर) का उपयोग करना चाहिए। उचित प्रशिक्षण तो जरूरी है ही।सीवर को साफ करने से पहले, उसका अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुरक्षित रूप से साफ किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सीवर में काम करने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर निकासी करनी चाहिए, ताकि वे थकान से बच सकें और उन्हें ताजी हवा(आक्सीजन) मिल सके। जेटिंग मशीन,स्नेकिंग उपकरण(जो सीवर में एक धातु की छड़ डालकर रुकावटों को तोड़ता है), तथा अन्य आधुनिक मशीनों जैसे कि रोबोटिक उपकणों आदि का प्रयोग किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही किसी भी सीवर को साफ करने के बाद, उसे ठीक से बंद करना चाहिए। कहना ग़लत नहीं होगा कि सीवर में काम करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना बहुत आवश्यक है।सीवर सफाई के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना या मृत्यु के मामले में, प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवारों को समय पर उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि हमारे देश की शीर्ष अदालत ने वर्ष 2023 में केंद्र और राज्यों को उचित उपाय करने, नीतियां बनाने और निर्देश जारी करने का निर्देश दिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मैनुअल सीवर सफाई को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इतना ही नहीं,उस समय माननीय न्यायालय ने कई निर्देश जारी करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से सीवर की सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने को भी कहा था। इतना ही नहीं,न्यायालय ने उस समय आगे यह भी निर्देश दिया था कि किसी भी विकलांगता से पीड़ित सीवर पीड़ितों के मामले में न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा। माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि विकलांगता स्थायी थी और पीड़ित आर्थिक रूप से असहाय हो गया था, तो मुआवजा 20 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अंत में यही कहूंगा कि आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं और पारंपरिक तरीकों से सीवरेज की साफ-सफाई पर अब पूरी तरह से अंकुश लगना चाहिए, ताकि हमें सीवरेज से मौतों के हादसे न देखने को मिलें। वास्तव में आज जरूरत इस बात की है कि हम सीवर में साफ-सफाई करने उतरे मजदूरों की जोखिम भरी जिंदगी और इस काम में उनके अस्तित्व और गरिमा के सवाल पर चिन्तन-मनन करें और इस दिशा में आवश्यक और जरूरी कदम उठाएं। यह बहुत ही अफसोसजनक है कि आजादी के सात दशक बाद आज जब हम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू चुके हैं, चांद सूरज पर अनुसंधान कर रहे हैं, एआइ युग में जी रहे हैं, ऐसे में अक्सर सीवर की साफ-सफाई के लिए उसमें उतरे मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। वास्तव में, इस समस्या के पीड़ितों या यूं कहें कि आमतौर पर समाज के सबसे कमजोर तबके से आने वाले लोगों पर हो रही अमानवीयता पर और अधिक चिंतन-मनन होना चाहिए।

–सुनील कुमार महला

सिचुएशनशिप: रिश्ता जिसमें किन्तु-परन्तु नहीं

सचिन त्रिपाठी

प्रेम संबंधों की परिभाषाएं समय के साथ बदलती रही हैं। पहले 'प्रेम' एक स्थायी, सामाजिक और पारिवारिक स्वीकृति वाला संबंध था। फिर प्रेम विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और अब 'सिचुएशनशिप' जैसे नए रूप सामने आए हैं। सिचुएशनशिप कोई पारंपरिक प्रेम संबंध नहीं है, न ही यह पूर्णतः मित्रता है। यह उन दो लोगों के बीच का अनिश्चित-सा, पर भावनात्मक रूप से गहरा जुड़ा हुआ रिश्ता है जिसमें स्पष्टता की बजाय धुंध, स्थायित्व की जगह अस्थाई होना और भरोसे की जगह संभावनाएं होती हैं लेकिन क्या सिचुएशनशिप सिर्फ भ्रम है? या यह आज की पीढ़ी का आत्म-स्वतंत्र और यथार्थवादी प्रेम है? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमें इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को गहराई से समझना होगा।

आज के युवा स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हैं चाहे वह करियर हो, स्थान चयन हो या रिश्ते। सिचुएशनशिप इस आज़ादी को जगह देता है। इसमें दोनों व्यक्ति एक-दूसरे की कंपनी पसंद करते हैं, लेकिन अपने जीवन के निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। कोई सामाजिक दबाव नहीं, न ही विवाह का अनावश्यक तनाव। यह रिश्ता उन्हें भावनात्मक संबल देता है जो अभी जीवन में स्थायित्व के लिए तैयार नहीं हैं। युवा जो पढ़ाई, करियर या निजी हीलिंग के दौर से गुजर रहे हैं, वे किसी गंभीर संबंध में बंधे बिना भी साथी के साथ जुड़ सकते हैं। अक्सर सिचुएशनशिप में दोनों पक्ष शुरू से स्पष्ट होते हैं कि वे अभी किसी परिभाषित रिश्ते में नहीं हैं। यह पारदर्शिता कई बार उस झूठ और छल से बेहतर होती है जो परंपरागत प्रेम संबंधों में दिखावे के रूप में होता है। आज की पीढ़ी अपने करियर और आत्म-विकास को पहले स्थान पर रखती है। विवाह या रिश्तों की स्थायित्वपूर्ण जिम्मेदारियों को टालते हुए भी वे एक भावनात्मक सहारा चाहते हैं। सिचुएशनशिप इस जरूरत को पूरा करता है।

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें न कोई वचन होता है, न कोई भविष्य की रूपरेखा। कई बार एक व्यक्ति अधिक जुड़ जाता है जबकि दूसरा असमंजस में रहता है। इससे भावनात्मक असुरक्षा, ईर्ष्या और दुख जन्म लेते हैं। सिचुएशनशिप में वर्षों निकल जाते हैं, और जब अंत में कोई एक व्यक्ति दूर चला जाए तो दूसरे के लिए यह गहरे आघात का कारण बनता है। कई युवाओं के लिए यह एक 'इमोशनल इंवेस्टमेंट' होता है जिसकी कोई निश्चित परिणति नहीं होती। भले ही शहरी युवा वर्ग इसे स्वीकार कर चुका हो, लेकिन सामाजिक ढांचे में यह अब भी अजीब या 'अधूरा' माना जाता है।

परिवार, समाज और रिश्तेदारों के सवालों का उत्तर नहीं होताः 'क्या चल रहा है?' 'क्या रिश्ता है?' "कब शादी करोगे?' बहुत से लोग सिचुएशनशिप की आड़ में किसी को 'टाइम पास' समझने लगते हैं। वे यह रिश्ता तब तक बनाए रखते हैं जब तक कोई बेहतर विकल्प न मिल जाए। इसमें भावनात्मक धोखा मिलने की संभावना बहुत अधिक रहती है।

भारत में मेट्रो शहरों, विश्वविद्यालय परिसरों और मल्टीनेशनल कंपनियों के युवाओं में यह रिश्ता तेजी से बढ़ रहा है। टिंडर, बम्बल जैसे डेटिंग ऐप्स पर कई युवा अब 'सिचुएशनशिप' को रिश्ता मानते हैं। 2024 के एक ऑनलाइन सर्वे के अनुसार, 18 से 30 वर्ष की आयु के 42% युवाओं ने स्वीकार किया कि वे 'डेट कर रहे हैं पर कमिटेड नहीं हैं'। इसका अर्थ स्पष्ट है; रिश्तों की दिशा बदल रही है। हाल ही में एक सोशल मीडिया घटना वायरल हुई जहां एक युवती ने 'ब्रेकअप नहीं हुआ पर अब हम स्ट्रेंजर हैं' जैसी पोस्ट लिखी। इसने हज़ारों युवाओं के दिल की आवाज़ को शब्द दे दिए।

क्या यह संबंध भविष्य है? इसका उत्तर 'हां' और 'ना' दोनों हो सकता है। हां, क्योंकि यह उन युवाओं के लिए एक विकल्प है जो फिलहाल स्थायित्व नहीं चाहते, पर अकेलेपन से जूझ रहे हैं।

सात दिन पूर्व जब प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा मुझे तो महाप्रभु के धरती पर जाना है .... जानिए ओडिशा की धरती को ,जानिए जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नीलचक्र को

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

सरायकेला , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथयात्रा के ठीक सप्ताह पूर्व ओडिशा आना, भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते यह कहना कि- ₹ मैंने भगवान जगन्नाथ की भूमि पर आने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका आने के न्यौते को नम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया₹ ।यह दो देशों के बीच कुटनीती एवं धार्मिक आस्था भले ही लगे पर ओड़िया भाषा में एक कहावत है ₹कालिया डोरि जेबे लागिबो ₹ यानी जगन्नाथ जी का बुलावा जब होता वह शख्स सबकुछ छोड़ हाजिरी लगाने पहुंच जाता । संभवत मोदी जी के साथ भी यही हुआ होगा ।जगन्नाथ की धरती यानी रथ पर्व -भारतीय पौराणिक समर इतिहास में रथ को युद्ध विमान का भी दर्जा प्राप्त है । जहां मंदिर के गुंबद पर विराजमान चक्र महाभारत का सर्वाधिक वड़ा आयुध वह महाभारत युद्ध का भी ।जिसके धारक महान कुटनीतिज्ञ कृष्ण का आज आप जगन्नाथ के रूप में ओडिशा में है ।

उधर पुरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र होता है उसे ही नीलचक्र कहा जाता ।वस्तुत यह एक आयुध है , जिसे जगन्नाथ के पास रहने पर चतुर्धामूर्ति का स्थान प्राप्त है, रत्न सिंहासन पर । पर इसका संबंध सीधे महाभारत युद्ध से है ।अगर हम ओडिशा के समर साहित्य मे शुद्र मुनी सारला दास के महाभारत को ले या कन्हाई चंपच राय के पाईक खेदा जैसे प्राचीन ताड़ पत्ते का ग्रन्थ को दोनों में उस चीलचक्र को महत्वपूर्ण स्थान दी गयी है । एक ने तो इसे महाभारत युद्ध के समय उस चक्रव्यूह का प्रतीक माना है जिससे कई वीर , वीर गति को प्राप्त हुए थे । महाभारत के रचनाकार स्वयं व्यासजी ने कलिंग के राजकुमारी भानुमती के भाई भानुमान एवं भीम के बीच लड़ाई में भानुमान के वीरता को लेकर भीष्म पर्व में कुल 72 श्लोक लिखकर कलिंग के प्रशंसा के पुल बांधे है ।जिस धरती पर आज महाभारत के सुत्र धार श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में पूजा ग्रहण करते ।

उसी महाभारत युद्ध से संबंध रखने वाले कलिंग के खंडायत पाइक संप्रदाय से आये कन्हेई चंपत राय ने भी अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ₹ पाइक खेदा₹ में नीलचक्र जो एक तरह का आयुध है उसमें बेहद दिलचस्प वर्णन किया है ।

अष्ट्रधातु निर्मित यह चक्र सूर्योदय के समय सफेद रंग जैसा दिखता है फिर इसका रंग बदल कर हल्का नीला हो जाता है। दोपहर के समय गहरा नीला। सूर्यास्त के समय इसका रंग बैंगनी जैसा हो जाता है जो बेहद आकर्षक प्रतित होता ।वैसे पहला नीला चक्र नष्ट कर दिया गया था और उसका कई बार पुनर्निर्माण किया गया ।1594 में राजा रामचंद्र देव के काल में इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसे मंदिर के शीर्ष पर परीच्छा बड़ो जेना महापात्र के पुत्र दामोदर चंपतिराय द्वारा स्थापित किया गया।

पुनः वर्ष 06-10-1694 में भारी चक्रवात के कारण कांची गणेश मंदिर के सामने नीला चक्र गिर गया और मंदिर कुछ वर्षों तक नीला चक्र के बिना रहा। इसके बाद नीलचक्र का निर्माण पुनः हुआ लगाया गया ।

ओडिशा के अतीत के पाइक अखाड़ों में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के दोनो भाईयों को बड़ा पाइक छोटा पाइक कह कर पूजा की जाती ।इतना ही नहीं ओड़िआ खंडायत परिवारों में इस चक्र को महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है ढाल -तलवारें के साथ ।

अगर ये अमेरिका के राईट बंधुओं द्वारा 1903 मे हवाई जहाज बनाने से पहले कहीं भारत के शिवकर बापूजी तलपदे ने 1895 में विमान बनाकर उड़ाया था तो हमें हमारी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित सिद्धान्तों पर गर्व होनी चाहिए जिसे ऋषियों द्वारा विमान शास्त्र प्रतिपादित फार्मूले पर तिलपदे ने उसका सफल प्रमाण कर दुनिया में भारतीय की देन विमान का उम्दा प्रमाण एहसास कराया था। जब आज हम 5वीं, 6ठी जेनरेशन के लड़ाकु विमान के लिए दुसरे से तरस रहे हैं ।यद्यपि हम अपने अतीत से कोई सीख नहीं लेते ।

हमें गर्व उस प्रधानमंत्री मोदी पर भी होनी चाहिए जिन्होंने दो टूक जबाब देकर 7 दिन पहले भूवनेश्वर में कहा-₹ मैं कनाडा में जी-7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर जाइए। उन्होंने बहुत आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया।

दिगंबर जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज की जयंती पर फिर उनकी अभिव्यक्ति याद आ रही है। सच्चाई का कच्चा चिट्ठा है उनकी कविता।

दिवंगत जैन मुनि तरुण सागर जी द्वारा रचित कविता ₹आदमी की औकात ।

फिर घमंड कैसा
घी का एक लोटा,
लकड़ियों का ढेर,
कुछ मिनटों में राख.....
बस इतनी-सी है
आदमी की औकात !!!!

एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया,
अपनी सारी ज़िन्दिगी,
परिवार के नाम कर गया,
कहीं रोने की सुगबुगाहट,
तो कहीं ये फुसफुसाहट....
अरे जल्दी ले चलो
कौन रखेगा सारी रात.....
बस इतनी-सी है
*आदमी की औकात !!!!

मरने के बाद नीचे देखा तो
नज़ारे नज़र आ रहे थे,
मेरी मौत पे.....
कुछ लोग ज़बरदस्त,
तो कुछ ज़बरदस्ती
रोए जा रहे थे।
नहीं रहा........चला गया.....
दो चार दिन करेंगे बात.....
बस इतनी-सी है
*आदमी की औकात !!!!

बेटा अच्छी सी तस्वीर बनवायेगा,
उसके सामने अगरबत्ती जलायेगा,
खुश्बुदार फूलों की माला होगी....
अखबार में अश्रुपूरित श्रद्धांजली होगी.........
बाद में शायद कोई उस तस्वीर के
जाले भी नही करेगा साफ़....
बस इतनी-सी है
*आदमी की औकात ! ! ! !

जिन्दगी भर,
मेरा- मेरा- किया....
अपने लिए कम ,
अपनों के लिए ज्यादा जिया....
फिर भी कोई न देगा साथ.....
जाना है खाली हाथ.... क्या तिनका ले जाने के लायक भी,
होंगे हमारे हाथ ??? बस
ये है हमारी औकात....!!!!

जाने कौन सी शोहरत पर,
आदमी को नाज है !*
जो आखरी सफर के लिए भी,
औरों का मोहताज है !!!!

फिर घमंड कैसा ?

बस इतनी सी हैं
हमारी औकात...
संकलनकर्ता हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

कानपुर में छात्र को साथ ले गई , रफ्तार रूपी मौत, साथी मरणासन्न

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां रफ्तार के रूप में मौत का कहर लगातार जारी है, जिसके क्रम में उसने एक छात्र की भी जान ले ली। वह अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। घटना महाराजपुर थानाक्षेत्र में बौसर गांव के पास ओवरटेक के दौरान हुई। यहां पिकअप ने बाइक सवार दो दोस्तों को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई। वहीं दोस्त की हालत गंभीर बनी हुई है।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को दूहरपुर, बांग्ला निवासी किसान शिवबाबू ने बताया कि उनका बेटा आयुष यादव (17) कक्षा नौ का छात्र था। साथ ही खेती किसानी में हाथ बंटाता था। घटना के समय आयुष अपने दोस्त सुमित के साथ बाइक से इकघरा से होते हुए साढ़ जा रहा था।

जानकारी केमुताबिक अभी वह महाराजपुर स्थित बौसर गांव के पास पहुंचा ही था कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप सवार ने लापरवाही से ओवरटेक करने में बाइक सवारों को टक्कर मार दी। जिसमें गंभीर दशा मेंदोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया ,जहां आयुष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर वाहन चालक की तलाश कर रही है।

अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम युग...!

भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम युग,
शुभांशु शुक्ला की अमर उड़ान का हैं मृग।
सीमाओं को तोड़कर अनंत की ओर बढ़ते,
विज्ञान एवं विरासत की संगम यात्रा चढ़ते।
ये करोडों दिलों की धड़कनों का उत्सव था,
सांस्कृतिक विरासत ब्रह्मांड में 'तिरंगा' था।
भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम युग,
शुभांशु शुक्ला की अमर उड़ान का हैं मृग।
यह भारत की जिजीविषा का ही प्रतीक है,
सितारों के उस पार पहचान 'अमरदीप' हैं।
साढ़े सात किलोमीटर प्रति सेकंड की गति,
पृथ्वी की परिक्रमा करते हो रहीं थी प्रगति।
भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम युग,
शुभांशु शुक्ला की अमर उड़ान का हैं मृग।
14 दिवसीय यात्रा वैज्ञानिक प्रयोग मिशन,
60 से ज्यादा प्रयोगों का ज़बरदस्त सेशन।
भारत के भविष्य अंतरिक्ष सपनों की धार,
शुभांशु लाखों 'तरुणाई' की प्रेरणा आधार।
–संजय एम तराणेकर

जग के नाथ जगन्नाथ

शरण में जो आए, प्रभु तारते हैं।
दया दृष्टि से ही संकट हरते हैं।
रथ में विराजे, नगर घूमते हैं।
कृपा से सभी को नव जन्म देते हैं॥

सुभद्रा समेतें, बलदेव साथे।
भक्ति में लहरें, जन मोद पाथे।
ध्वज और पताका, शुभ चित्त राखे।
पवित्र पथों पर चरण प्रभु राखे॥

पट जब खुले तो हृदय नाचे रे।
भीड़ें उमड़तीं, सभी गाएँ रे।
रथ खींच भक्तों का मन भाए रे।
मोक्षोपथ खुद प्रभु बतलाएँ रे॥

कालों में कलि का ये नाथ जग है।
केशव का साक्षात रूप रथ मग है।
हरि नाम से ही तो भक्ति उमग है।
रथयात्रा चेतन पथ की सजग है॥

सागर समर्पण, चरणों पे होवे।
मन मन्दिरों में प्रभु प्रेम रोवे।
जग के अधीशा, कृपा की शोभा।
जगन्नाथ ही तो शरण हैं लोभा॥

समुद्री व्यापार में ओडिशा की हिस्सेदारी बढ़ेगी, 8 और छोटे बंदरगाह स्थापित किए जाएंगे

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : ओडिशा घरेलू बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के समुद्री व्यापार में राज्य की हिस्सेदारी फिलहाल 13% है। इसे बढ़ाकर 33% किया जाएगा। प्रमुख बंदरगाहों का विस्तार किया जाएगा और 2047 तक सालाना 500 मिलियन टन माल संभालने के लिए 8 नए गैर-प्रमुख बंदरगाह स्थापित किए जाएंगे।इसी तरह, राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट में जेटी और संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2036 और 2047 का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में, राज्य के बंदरगाहों ने सामूहिक रूप से 190 मिलियन टन माल की ढुलाई की है। यह 2047 तक बढ़कर 500 से 600 मिलियन टन हो जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार पूरे बंदरगाह बुनियादी ढांचे में निवेश और विस्तार, आधुनिक तकनीक का उपयोग, डेटा-आधारित कार्यान्वयन को मजबूत करने, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने, बाधा मुक्त डेटा एक्सचेंज, विश्लेषणात्मक सहयोग और संचालन की समग्र दक्षता पर ध्यान केंद्रित करेगी। पारादीप, धामरा और गोपालपुर बंदरगाहों के विस्तार के अलावा, अस्तरंगा, सुब्रनरेखा, इंचुडी, बाहुदा जैसे

स्थानों पर नए बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य शिपिंग के विकास के लिए राज्य के भीतर जलमार्गों को विकसित करके माल के परिवहन में तेजी लाना है। डेवलपर्स, ट्रांसपोर्टरों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके एनडब्ल्यू-5 और एनडब्ल्यू-64 का विकास किया जाएगा। राज्य सरकार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जलमार्गों की पूरी क्षमता का पता लगाएगी। इसका उद्देश्य तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) के लिए समुद्री तटीय क्षेत्रीय योजना (एमसीआरपी) के माध्यम से बंदरगाह आधारित विकास को सक्षम करना है, जिसका लक्ष्य 2047 तक एक तिहाई कार्गो परिवहन है। इसी तरह, गैर-प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाकर 2 मिलियन टन किया जाएगा। 2047 तक 5 लाख करोड़ रुपये के जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में समर्पित समुद्री अध्ययन विभाग अनुसंधान, नवाचार और साझेदारी आधारित कार्यक्रम शुरू करेगा। वर्तमान में सुनार रेखा और अस्तरंगा बंदरगाहों के काम में तेजी लाई गई है। जानकारी के अनुसार, पारादीप पोर्ट अब 150 मिलियन टन से अधिक कार्गो परिवहन करने में सक्षम है। इसी तरह, धामरा ने 43 मिलियन टन कार्गो को संभाला है। 2023-24 में राज्य के बंदरगाहों ने मिलकर 190 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया। चूंकि ओडिशा देश के पूर्वी हिस्से, आसियान और इंडो-पैसिफिक व्यापार मार्गों पर स्थित है, इसलिए समुद्री परिवहन क्षेत्र के विकास से राज्य के लिए नए अवसर पैदा होंगे। पारादीप बंदरगाह पहले ही इस क्षेत्र में एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित हो चुका है। पारादीप-हरिदासपुर, तालचेर-अंगुल-कलिंगनगर औद्योगिक पार्क के विकास से बंदरगाह आधारित कार्गो परिवहन में तेजी आने की उम्मीद है। अडानी जैसी प्रमुख बंदरगाह कंपनियों द्वारा राज्य में निवेश किए जाने से स्वचालन और एलएनजी क्षेत्रों में तेजी आई है। राज्य सरकार की योजना से राज्य के समुद्री उद्योग को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023